18 जुलाई, 2026 शनिवार
नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 107

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान ने कसा टीम इंडिया पर तंज 07

भारत को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन: पीएम मोदी ने जींद से दिखाई हरी झंडी

जींद से सोनीपत के बीच चलेगी देश की पहली पर्यावरण अनुकूल ट्रेन - महज 25 रुपये में पूरा होगा 2 घंटे का सफर, रास्ते में होंगे 14 स्टॉपेज

वेब वार्ता, जींद। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली 'हाइड्रोजन-पावर्ड' (हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली) ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हरियाणा और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी।

इस ऐतिहासिक शुरूआत के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ट्रेन चलाने के लिए हाइड्रोजन को ईंधन (फ्यूल) के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पहल देश में ग्रीन मोबिलिटी (हरित परिवहन) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश की यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। इसका संचालन ट्रेन नंबर 74010 और 74009 के रूप में किया जाएगा। यह ट्रेन रोजाना सुबह 7:40 बजे जींद से रवाना होगी और 2 घंटे का समय लेकर सुबह 9:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन सुबह 10:30 बजे सोनीपत से चलेगी और दोपहर 1:00 बजे जींद पहुंचेगी। सफर के दौरान ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस आधुनिक और इको-फ्रेंडली ट्रेन का किराया बेहद कम रखा गया है । न्यूनतम किराया मात्र 5 रुपये (एक स्टेशन से अगले स्टेशन के लिए) तय किया गया है।

सभी स्टेशनों में रूकते हुए आयेगी वापस

जींद से सोनीपत के बीच के सफर में यह ट्रेन कुल 14 स्टेशनों पर ठहराव करेगी जींद जंक्शन (प्रस्थान) के बाद जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंभेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रभड़ा, लाठ, मोहाना, बड़वासनी, सोनीपत जंक्शन पहुंचेगी वापसी यात्रा में भी ट्रेन इन्हीं स्टेशनों पर रुकते हुए वापस आएगी।

भारत की नजरङ्ग पहले आर्मी चीफ, अब अमित शाह का बॉर्डर दौरा

वेब वार्ता, नई दिल्ली। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान का रवैया भारत के प्रति षड्यंत्रकारी बताया जा रहा है। उन्होंने परंपराओं को दरकिनार करते हुए अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही ढाका के अधिकारी चीन को सीमावर्ती इलाकों में पैर जमाने के लिए जमीन मुहैया कराने में लगे हुए हैं। चाहे वह तीस्ता प्रोजेक्ट हो या लालमोनिरहाट एयरबेस को विकसित करने की योजना, हर जगह चीन को आमंत्रित किया जा रहा है।

संक्षिप्त वार्ता

न्यूजीलैंड में एच5एन1 वायरल की दस्तक

वेलिंगटन। एक सीनियर वेटेरिनरी अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को न्यूजीलैंड में एक जंगली समुद्री पक्षी में एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा का नया स्ट्रेन मिलने के बाद, इसके कुछ ही महीनों में देश में स्थानिक बीमारी बनने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज की चीफ वेटेरिनरी ऑफिसर ने बताया कि अगर यह वायरस जंगली जीवों में फैल गया, तो इसे खत्म करना मुश्किल होगा। वेलिंगटन के पेटोन बीच पर मिले एक समुद्री पक्षी में एच5 वायरस की पुष्टि हुई है। यह दुनिया भर में जंगली पक्षियों के बीच फैले इस वायरस का न्यूजीलैंड में पहला मामला है।

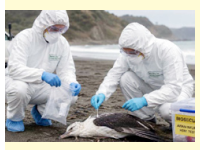

रिपोर्ट के मुताबिक ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की प्रोफेसर ने कहा कि न्यूजीलैंड का अलग-थलग होना इस जानलेवा बर्ड वायरस को नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी जंगली जीवों की बड़े पैमाने पर मौत या न्यूजीलैंड के पक्षियों के बीच इसके फैलने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन समय के साथ एच5एन1 के यहां फैलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वायरस पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और इससे खाद्य सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता है।

महाराष्ट्र में इच्छामृत्यु और लिविंग विल पर बड़ा फैसला

मुम्बई। महाराष्ट्र सरकार ने मरीजों के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु और लिविंग विल से जुड़े नियमों का दायरा बढ़ाते हुए इन्हें अब सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी लागू करने का आदेश जारी किया है. इसके लिए आवश्यक समितियों के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्णय लिए जा सकें. सरकार का मानना है कि इस कदम से जीवन के अंतिम चरण में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अस्पतालों में एक समान व्यवस्था लागू की जा सकेगी.

लद्दाख में शुरू हुआ भारत का सबसे व्यावसायिक लिलियम फूलों का खेत

लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित व्यावसायिक लिलियम फूलों के खेत के विकास की शुरूआत हो गई है. लेह के चोगलामसर में सिंधु नदी के किनारे विकसित किए जा रहे इस फ्लोरीकल्चर प्रोजेक्ट का उद्देश्य किसानों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के लिए आय के नए और टिकाऊ स्रोत तैयार करना है. करीब 3,265 मीटर की ऊंचाई पर विकसित हो रहा यह फ्लावर फील्ड देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित संगठित व्यावसायिक फूलों का पार्क होगा. इससे पहले उत्तराखंड के माणा में 3,200 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचाई वाला फ्लावर फील्ड मौजूद है. करीब 93,000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट में पिछले तीन दिनों के दौरान 50 हजार से अधिक प्रीमियम लिलियम बल्ब लगाए जा चुके हैं. इन फूलों की पहली खेप सितंबर के पहले सप्ताह तक खिलने की उम्मीद है.

दान चोरी: बाथरूम में मिले 40 हजार, गार्ड की ईमानदारी से खुला मामला

वेब वार्ता, अयोध्या। राम मंदिर दान चोरी मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें शेयर मार्केट से लेकर कई अन्य लिंक सामने आ रहे हैं। अब तक इस मामले में आठ लोगों पर पुलिस की तलवार लटक चुकी है और नए नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बड़े घोटाले का खुलासा किसी शिकायत से नहीं, बल्कि एक साधारण चौकीदार की ईमानदारी से हुआ। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मई के अंतिम सप्ताह में मंदिर परिसर के एक बाथरूम में करीब 40 हजार रुपये की नकदी छिपाकर रखी गई थी। गेट पर तैनात एक गार्ड की नजर इस पर पड़ी और उसने तुरंत श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक ट्रस्टी को इसकी सूचना दी।

गार्ड की सूचना मिलते ही ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी मंदिर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों व अन्य ट्रस्टियों को इस बारे में जानकारी दी। शुरूआती जांच में ही दान पेटियों से आने वाली नकदी में भारी गड़बड़ी की आशंका सामने आ गई। इसके बाद ट्रस्ट ने पहले एक आंतरिक जांच शुरू की और फिर 4 जून को जिला प्रशासन को पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी, जिसके बाद औपचारिक आपराधिक जांच का रास्ता खुल गया। सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सूचना मिलने के बाद 21 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। इस टीम ने दान गिनने की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की, संबंधित कर्मचारियों से गहन पूछताछ की और पुलिस को आवश्यक जानकारी प्रदान की, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई।

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक कहा- कानून के दायरे में ही चलेगा बुलडोजर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि कानून के लिए बुलडोजर चल सकता है, लेकिन इसका उपयोग चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि उसके पहले के फैसले में सभी बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक नहीं लगाई गई थी, बल्कि यह सुनिश्चित किया गया था कि तोड़-फोड़ की कार्रवाई कानून और संविधान के दायरे में ही हो। यह टिप्पणी मनमाने ढंग से बुलडोजर एक्शन के आरोपों वाली अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि हर बुलडोजर एक्शन की वैधता की जांच उसके अपने तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए और ऐसे मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट ही सही जगह है। बेंच ने अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि उठाए गए मुद्दों में तथ्यों से जुड़े विवादित सवाल शामिल हैं, जिनकी विस्तार से जांच की आवश्यकता है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल सही हो सकता है, विशेषकर जब अधिकारियों और अवैध कब्जा करने वालों की मिलीभगत से कानून का शासन कमजोर हो रहा हो।

अमेरिका ने ईरान के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पुल कर दिए तबाह

वेब वार्ता, वॉशिंगटन

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुँच गया है, जहाँ अमेरिका ने ईरान पर लगातार छठे दिन भी भीषण हमले किए हैं। गुरुवार रात को, अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें पुल, रेलवे स्टेशन, पावर प्लांट और दूरसंचार टावर तबाह हो गए। रिपोर्टों के अनुसार, इन हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुँचाना प्रतीत होता है। गुरुवार को ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, जॉर्डन और कुवैत जैसे पड़ोसी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य और ढाँचागत क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, अमेरिका ने होर्मुज क्षेत्र में भी कई हमले किए हैं। दक्षिणी ईरान के इरानशहर एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाके सुने गए, जहाँ मिसाइल हमलों की पुष्टि हुई है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागीं। इसके अलावा, बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में स्थित रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है, जिससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि होर्मुजगैन प्रांत में बंदर खमीर के पास दो पुलों पर भी हमले हुए हैं। इन हमलों में करीब दो लोगों के मारे जाने और चार के घायल होने की खबर है, जिसके बाद बंदर अब्बास को जोड़ने वाले खमीर और लार के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हमलों का सिलसिला यहीं नहीं रुका; दक्षिणी ईरान के केश्म आइलैंड पर भी बमबारी की गई। बंदर अब्बास के एक मोबाइल टावर को भी भारी नुकसान पहुँचा है, जिससे इस इलाके में मोबाइल सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस हमले में सात लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो दर्शाता है कि अमेरिकी हमले कितने व्यापक और गंभीर थे। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद हुए हैं, जिसमें उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य को सबके लिए पूरी तरह नहीं खोला जाता है, तो घुसकर उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा।

कोरोना की वापसी की आशंका: 4 मौतें और 12 नए केस से हड़कंप

वेब वार्ता, नई दिल्ली

देश में कोविड-19 के कुछ नए मामलों और मौतों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, जिससे बीमारी की वापसी का खतरा मंडराने लगा है। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच 12 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जिनमें से चार मरीजों की पहले से मौजूद गंभीर बीमारियों और कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। इन मौतों का अनुपात लगभग 30 प्रतिशत रहा, जिसने लोगों को विशेष रूप से भयभीत कर दिया है। मरने वाले मरीजों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज और किडनी संबंधी गंभीर समस्याएं थीं। शेष संक्रमितों में से तीन होम आइसोलेशन में हैं, दो अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि तीन ठीक होकर घर जा चुके हैं। जुलाई के पहले पखवाड़े में देशभर में कुल 339 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जो सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

हालांकि, संक्रामक रोग विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल देश में कोरोना की कोई नई लहर नहीं है और न ही कोई खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। आंध्र प्रदेश के मामले स्थानीय क्लस्टर प्रतीत होते हैं, न कि देशव्यापी फैलाव। जानकार बताते हैं कि एक बड़ी आबादी में अब हाइब्रिड इम्यूनिटी मौजूद है, जो गंभीर बीमारी से बचाती है।

इन्फ्लूएंजा और कोविड के लक्षण मिलते-जुलते हैं, इसलिए जांच महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशेष रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। यदि बुखार 3-5 दिन से अधिक रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दर्द हो या भ्रम बढ़े, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मास्क के उपयोग पर विशेषज्ञों का कहना है कि हर किसी को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि किसी को बुखार, खांसी, गले में खराश या नाक बह रही है, तो दूसरों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क जरूर पहनें।

सतर्कता और सावधानी ही सर्वोत्तम उपाय

अस्पताल जाते समय या भीड़भाड़ वाली बसों, ट्रेनों और फ्लाइट्स में भी मास्क का उपयोग करना उचित है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारियों वाले लोगों को भीड़ वाली बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ जरूरी सावधानियों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, बाहर से आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से धोना, खांसी या जुकाम होने पर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। यदि बच्चे बीमार हों, तो उन्हें स्कूल या खेलने न भेजें और घर पर उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था बनाए रखें। घबराने के बजाय सतर्कता और सावधानी ही इस स्थिति से निपटने का सर्वोत्तम उपाय है।

आचार्य श्री चैत्य सागर सहित आठ संतो का हुआ मंगल प्रवेश

वेब वार्ता, ग्वालियर। ग्वालियर दिगंबर सकल जैन समाज की ओर से आचार्यश्री विमल सागर महाराज के शिष्य आचार्य श्री चैत्य सागर महाराज ओर मुनिश्री अनुमान सागर महाराज ससंघ का ग्वालियर की पवन धरा पर आठ संतो का एक साथ भव्य मंगल प्रवेश शोभायात्रा आज शुक्रवार को खासगी बाजार स्थित दिगंबर आदिनाथ जैन मंदिर से निकाली गई। आचार्य श्री चैत्य सागर महाराज ओर अनुमान सागर महाराज ससंघ की आगवानी सम्पूर्ण ग्वालियर सकल जैन समाज ने सम्मिलित होकर जयकारों के साथ की।

जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि आचार्य श्री चैत्य सागर महाराज, मुनिश्री अनुमान सागर महाराज, गणिनी आर्यिका श्री शाश्वत श्री माताजी, आर्यिका श्री स्वात्मश्री माताजी, आर्यिका श्री पुरुषार्थ श्री माताजी, आर्यिका श्री समवशरण श्री माताजी, ऐलक श्री उत्सव सागर महाराज एवं क्षुल्लक श्री अरति सागर महाराज ससंघ की मंगल प्रवेश शोभायात्रा खासगी बाजार स्थित दिगंबर आदिनाथ जैन मंदिर से शुरू हुई। इस शोभायात्रा में सबसे आगे युवा हाथों में जैन ध्वजा लेकर चल रहे थे। वही ढोल ताशे पर भजनों पर युवक और युवतियां जमकर नृत्य कर रहे थे। शोभायात्रा में महिलाएं केसरिया साड़ी और पुरुष व्हाइट परिधानों में सम्मिलित हुए। वही आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने सभी भक्तो को आशीर्वाद देते हुए चल रहे थे। मंगल प्रवेश शोभायात्रा खासगी बाजार जैन मंदिर से शुरू होकर गांधी मार्केट, मोर बाजार, दाना ओली से नई सड़क स्थित कार्यकम स्थल चंपाबाग धर्मशाला पहुंची।

मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा प्लान

वेब वार्ता, नई दिल्ली। संसद के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरने की अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। गुरुवार को कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जिन्हें सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा।

इस बैठक में फैसला किया गया कि कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं, लगातार हो रहे पेपर लीक, राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी जैसे भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार से कड़ा जवाब मांगेगी। इसके अतिरिक्त, एथनॉल मिश्रण नीति, कमरतोड़ महंगाई, विदेश नीति की कथित विफलताएं, संस्थानों पर बढ़ते कब्जे और राजनीतिक दलों को तोड़ने की प्रवृत्ति को भी उठाया जाएगा। पार्टी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हो रहे लगातार हमलों तथा बेलगाम वनों की कटाई से जुड़े पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी सदन में उठाने का संकल्प लिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और राज्यसभा में मुख्य सचेतक जयराम रमेश सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने रणनीति बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पोस्ट कर इन जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार से जवाबदेही तय करने की बात कही। सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसद के भीतर विपक्षी दलों के साथ समन्वय स्थापित करने और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को प्रभावी ढंग से घेरने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने की संभावना है।

मोदी सरकार की घेराबंदी की तैयारी

वांगचुक ने कहा- तोड़ देंगे अनशन, पर 20 जुलाई के मार्च को सफल बनाना होगा!

वेब वार्ता, नई दिल्ली

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो पिछले बीस दिनों से जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, अब इसे खत्म करने को राजी हो गए हैं। हालांकि, उन्होंने यह शर्त सरकार के सामने नहीं, बल्कि जनता के सामने रखी है। वांगचुक ने संकेत दिया है कि यदि 20 जुलाई का संसद मार्च सफल होता है तो वह अपना अनशन समाप्त कर देंगे। उन्होंने देश भर के लोगों से इस मार्च को सफल बनाने की अपील की है।

वांगचुक ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि वे केवल अनशन खत्म करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि एक छोटा कदम उठाने के लिए कह रहे हैं, जिसमें मिस्ड कॉल करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना भी शामिल है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी माताओं को

साथ लेकर संसद तक मार्च करें। उन्होंने वादा किया कि यदि यह मार्च कामयाब रहा और मुद्दा सही हाथों में गया, तो वे चैन की नींद सो पाएंगे और अपना अनशन तोड़ देंगे। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह मार्च की सफलता के लिए क्या पैमाने मानेंगे, जैसे कितनी भीड़ या कितनी दूर तक मार्च कर पाना उनकी नजर में कामयाबी होगी। इस अनिश्चितता के बावजूद, उनका आह्वान जनता के सहयोग पर केंद्रित है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ मिल सके। अपने अनशन के 19वें दिन तक सोनम वांगचुक का वजन 9 किलो घट गया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि बहुत से लोग उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह कर रहे हैं। वांगचुक ने स्वीकार किया कि उनका शरीर कमजोर हुआ है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी हालत इतनी खराब नहीं है कि वे 3-4 दिन में मर जाएं। उन्होंने कहा कि वह अपना अनशन तभी खत्म करेंगे जब जनता एकजुटता दिखाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने लोगों से 20 जुलाई के संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से माताओं से इस मार्च का नेतृत्व करने की अपील की, यह कहते हुए कि बच्चों के लिए मां के दिल में जो प्यार होता है, वह किसी और के दिल में नहीं होता।

संपादकीय

ऑपरेशन दो-तिहाई अंजाम तक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने-अपने स्तर पर चाणक्य साबित कर दिया है। गृहमंत्री का ऑपरेशन दो-तिहाई लगभग अंजाम तक पहुंच चुका है और पवार ने परिसीमन संशोधन बिल को समर्थन का संकेत देकर अपने 8 सांसदों का दलबदल बचा लिया है। संभावनाएं बन रही हैं कि पवार एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के निदेर्शानुसार गृहमंत्री शाह का आग्रह है कि एनसीपी के दोनों गुट आपस में विलय कर एक संगठित पार्टी बनाएं और फिर एनडीए का हिस्सा बनें। एनसीपी का जो गुट दिवंगत अजित पवार के नेतृत्व में टूटा था, वह महाराष्ट्र और केंद्र में एनडीए का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने भी इसी गुट को असली एनसीपी की मान्यता दी है, लेकिन मामला अब भी सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है। बहरहाल ऑपरेशन दो-तिहाई प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भाजपा के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि बीती 17 अप्रैल को परिसीमन संशोधन बिल लोकसभा में परास्त हो गया था। मोदी सरकार के 12-साला कार्यकाल में यह पहली अत्यंत महत्वपूर्ण संसदीय पराजय थी, लिहाजा सरकार अब तभी यह संशोधन बिल संसद में लाएगी, जब लोकसभा में उसका दो-तिहाई बहुमत निश्चित हो जाएगा। संविधान संशोधन बिल को पारित कराने की यह संवैधानिक शर्त है कि दो-तिहाई बहुमत का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा में फिलहाल 540 सदस्य हैं, जिसका दो-तिहाई 360 सांसद बनता है, लेकिन बिल पारित कराने की संवैधानिक, संसदीय व्यवस्था यह है कि मतविभाजन के समय जितने सांसद सदन में हैं, उनका दो-तिहाई बहुमत होना लाजिमी है, लेकिन सदन में कमोबेश 50 फीसदी सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

लोकसभा में भाजपा के 240 सांसद हैं, लेकिन एनडीए के पक्ष में कुल 293 सांसद हैं। पिछली बार छोटे दलों के 5 सांसदों ने भी संविधान संशोधन बिल के समर्थन में मतदान किया था, लिहाजा एनडीए के 298 सांसद माने जा सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पालाबदल किया था, उसके बाद अब वे नेशनल सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के सांसद हैं। त्रिपुरा और बंगाल की यह बौनी-सी, गुमनाम पार्टी पहले से ही एनडीए की घटक है, लिहाजा ऑपरेशन दो-तिहाई के तहत इन 20 सांसदों को गिनते हुए एनडीए को 318 सांसदों का समर्थन हो जाता है। असली शिवसेना (एकनाथ शिंदे वाली) ने उद्धव गुट में सेंध लगाई और चाणक्य भाजपा की सहायता से 6 सांसदों को तोड़ कर पार्टी में शामिल भी कर लिया गया। नतीजतन एनडीए के 324 सांसद हो गए। अब गिद्ध-दृष्टि तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी द्रमुक पर है। पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन परिसीमन के साथ-साथ चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के भी घोर विरोधी रहे हैं। तमिलनाडु में द्रमुक सत्ता के बाहर हो चुकी है। लोकसभा में उसके 22 सांसद हैं। गौरतलब यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में, तत्कालीन द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधि की सहमति से, एनडीए और भारत सरकार में भाजपा-द्रमुक साथ-साथ रहे हैं। ऐसा कोई वैचारिक विभाजन नहीं है। दोनों के बीच कोई लक्ष्मण-रेखा भी नहीं है। हालांकि द्रमुक के कुछ नेताओं ने सनातन के लिए बेहद अभद्र, अश्लील, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। राजनीति में ऐसे आचरण, दुर्व्यवहार अक्सर भुला दिए जाते हैं। यदि द्रमुक के 22 सांसद लोकसभा में संशोधन बिल को समर्थन देते हैं, तो एनडीए के पक्ष में 346 सांसद हो सकते हैं। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसदों का समर्थन लगभग तय माना जा रहा है, लिहाजा सत्ता-पक्ष के 354 सांसद हो सकते हैं। यह कोई सामान्य संख्या नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ठीक ही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक देश का राजनीतिक नक्शा बदल देना चाहते हैं। चूंकि महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए देश में परिसीमन करना अनिवार्य है, लिहाजा नए बिल में ऐसा प्रावधान हो सकता है कि सभी राज्यों की 50 फीसदी लोकसभा सीटें बढ़ाई जाएंगी। परिसीमन उसी आधार पर किया जाएगा। इसमें किसी भी दल को क्या आपत्ति हो सकती है? विपक्ष की बात अलग है। बहरहाल भाजपा का ऑपरेशन तो कामयाब लगता है।

महंगाई, दोहरी आय और बदलता परिवार

आज के समय में यदि किसी मध्यमवर्गीय परिवार से पूछा जाए कि उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, तो उत्तर लगभग एक जैसा होगा—बच्चों की महंगी शिक्षा, घर का सपना, स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता खर्च और रोजमर्रा की बढ़ती महंगाई। एक साधारण नौकरीपेशा व्यक्ति वर्षों की बचत के बाद भी अपना घर नहीं खरीद पा रहा। निजी विद्यालयों की फीस इतनी अधिक हो चुकी है कि बच्चों की शिक्षा परिवार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हाल के वर्षों में एक विचार तेजी से चर्चा में आया है कि इन समस्याओं का प्रमुख कारण महिलाओं का बड़ी संख्या में कार्यक्षेत्र में आना है। तर्क दिया जाता है कि जब पति और पत्नी दोनों कमाने लगे तो परिवारों की कुल आय बढ़ गई। बाजार ने इसे अवसर मान लिया और मकानों, स्कूलों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के दाम बढ़ा दिए। इस विचार के समर्थक यह भी कहते हैं कि महिलाओं के घर से बाहर निकलने से परिवार कमजोर हुए, बच्चों का पालन-पोषण प्रभावित हुआ और समाज में अस्थिरता बढ़ी।

यह तर्क पहली नजर में कुछ लोगों को आकर्षक लग सकता है, क्योंकि वास्तव में आज अधिकांश शहरी परिवारों में एक आय से घर चलाना कठिन होता जा रहा है। किंतु किसी भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का विश्लेषण केवल एक कारण के आधार पर नहीं किया जा सकता। समाज, अर्थव्यवस्था और परिवार कई परस्पर जुड़े कारकों से प्रभावित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस बहस को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए। सबसे पहले यह समझना होगा कि भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में मकानों की कीमतें केवल परिवारों की आय बढ़ने से नहीं बढ़ीं। शहरीकरण, सीमित भूमि, बढ़ती आबादी, निवेश के रूप में रियल एस्टेट की लोकप्रियता, सरकारी नीतियां, निर्माण लागत, भूमि अधिग्रहण की जटिलताएं और आसान ऋण व्यवस्था जैसे अनेक कारणों ने संपत्ति की कीमतों को प्रभावित किया। यदि केवल महिलाओं के रोजगार से ही मकान महंगे हुए होते, तो जिन देशों में महिलाओं की श्रम भागीदारी अधिक है वहां आवास हमेशा सबसे महंगा होना चाहिए था, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है।

इसी प्रकार शिक्षा की बढ़ती लागत का संबंध भी अनेक कारणों से है। निजी शिक्षा का विस्तार, आधुनिक सुविधाओं की प्रतिस्पर्धा, अंग्रेजी माध्यम का आकर्षण, तकनीकी संसाधनों पर बढ़ता खर्च, शिक्षकों के वेतन, परिवहन, भवन निर्माण और शिक्षा के व्यवसायीकरण ने फीस बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कहना कि केवल इसलिए स्कूलों की फीस बढ़ी क्योंकि महिलाएं नौकरी करने लगीं, आर्थिक वास्तविकताओं का अत्यधिक सरलीकरण होगा। फिर भी इस विचार के पीछे एक महत्वपूर्ण चिंता अवश्य छिपी हुई है। वह चिंता है परिवार की बदलती संरचना और जीवन की गुणवत्ता। यह सत्य है कि पहले संयुक्त परिवारों में बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा और घरेलू जिम्मेदारियां साझा होती थीं। आज छोटे परिवारों में पति-पत्नी दोनों के कार्यरत होने पर समय का अभाव महसूस होता है। बच्चों के साथ बिताया जाने वाला समय कम हुआ है। तनाव, मानसिक दबाव और कार्य-जीवन संतुलन की समस्याएं बढ़ी हैं। लेकिन इन समस्याओं का समाधान महिलाओं को घर तक सीमित करना नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक और आर्थिक नीतियां बनाना है जो परिवार और कार्य के बीच संतुलन स्थापित कर सकें।

इतिहास भी इस विषय को उतनी सरलता से नहीं देखता जितना अक्सर सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं ने सदियों से खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, व्यापार और पारिवारिक व्यवसायों में योगदान दिया है। औद्योगिक क्रांति के दौरान भी बड़ी संख्या में महिलाएं कारखानों में कार्य करती थीं। इसलिए यह कहना कि इतिहास में महिलाएं हमेशा घर पर ही रहती थीं, वास्तविकता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। अंतर केवल इतना है कि पहले उनके श्रम का बड़ा हिस्सा बिना वेतन के घरेलू कार्यों में दिखाई देता था, जबकि आज वही श्रम वेतनभोगी रोजगार के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह भी सही है कि घरेलू कार्य का आर्थिक मूल्य अक्सर कम करके आंका गया है। घर संभालना, बच्चों का पालन-पोषण करना, बुजुर्गों की सेवा करना और परिवार की व्यवस्था बनाए रखना किसी भी समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। यदि कोई महिला या पुरुष यह भूमिका निभाता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसी प्रकार यदि कोई महिला अपनी शिक्षा, योग्यता और इच्छा के अनुसार नौकरी करना चाहती है तो उसके निर्णय का भी समान सम्मान होना चाहिए। वास्तविक सशक्तिकरण का अर्थ विकल्प का अधिकार है, न कि किसी एक जीवनशैली को सभी पर थोप देना।

आर्थिक दृष्टि से भी यह विचारणीय है कि यदि लाखों महिलाएं अचानक कार्यबल से बाहर हो जाएं तो देश की उत्पादन क्षमता, कर संग्रह, उपभोग और आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अनेक क्षेत्रों—शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन और वैज्ञानिक अनुसंधान—में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों से महिलाओं की अनुपस्थिति केवल परिवारों को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति को प्रभावित करेगी। वास्तविक समस्या शायद कहीं और है। पिछले कुछ दशकों में उत्पादकता जितनी बढ़ी, उतनी गति से आम नागरिक की वास्तविक क्रयशक्ति नहीं बढ़ी। संपत्ति कुछ हाथों में अधिक केंद्रित हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं का तेजी से निजीकरण हुआ। महानगरों में भूमि की उपलब्धता सीमित रही। निवेशकों ने आवास को रहने की आवश्यकता से अधिक निवेश का साधन बना दिया। परिणामस्वरूप मकान आम परिवार की पहुंच से दूर होते गए। इसी प्रकार शिक्षा सेवा न रहकर एक बड़े उद्योग का रूप लेती गई। इन संरचनात्मक कारणों की अनदेखी कर पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के रोजगार पर डाल देना समस्या का समाधान नहीं है।

निश्चित रूप से आधुनिक जीवनशैली ने परिवारों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। छोटे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, वैवाहिक संबंधों में संवाद की कमी और बढ़ता मानसिक तनाव वास्तविक समस्याएं हैं। इनका समाधान लचीले कार्य घंटे, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, गुणवत्तापूर्ण डे-केयर, परिवार समर्थक नीतियों और कार्यस्थलों पर संवेदनशील वातावरण से निकलेगा। केवल महिलाओं को दोषी ठहराने से न तो महंगाई कम होगी और न ही परिवार मजबूत होंगे। यह भी समझना होगा कि अनेक महिलाओं के लिए नौकरी कोई शौक नहीं बल्कि आवश्यकता है। बढ़ती महंगाई, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च, आवास ऋण और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के कारण दोहरी आय कई परिवारों की मजबूरी बन चुकी है। दूसरी ओर लाखों महिलाएं अपनी प्रतिभा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक योगदान के लिए भी कार्य करना चाहती हैं। उनके निर्णय को केवल बाजार की साजिश बताना उनके व्यक्तित्व और अधिकारों दोनों को सीमित करता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि समाज में पुरुष और महिला दोनों की भूमिकाएं बदल रही हैं। यदि दोनों कमाते हैं तो घरेलू जिम्मेदारियां भी दोनों को साझा करनी चाहिए। बच्चों का पालन-पोषण केवल मां का नहीं, पिता का भी समान दायित्व है। इसी प्रकार आर्थिक जिम्मेदारी केवल पुरुष की नहीं, बल्कि आवश्यकता और सहमति के अनुसार दोनों की हो सकती है। आधुनिक परिवार की सफलता इसी साझेदारी में निहित है।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता दोषारोपण की नहीं बल्कि संतुलन की है। हमें ऐसा समाज चाहिए जहां परिवार भी मजबूत हों और महिलाओं की प्रतिभा भी विकसित हो। जहां घरेलू कार्य का सम्मान हो और पेशेवर उपलब्धियों का भी। जहां बच्चों को माता-पिता दोनों का समय मिले और दोनों को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी। आर्थिक नीतियां ऐसी हों कि शिक्षा और आवास आम नागरिक की पहुंच में रहें। निजी संस्थानों पर प्रभावी नियमन हो, गुणवत्तापूर्ण सरकारी विद्यालय और अस्पताल मजबूत किए जाएं तथा आवास क्षेत्र में पारदर्शिता और किफायत सुनिश्चित की जाए। अंततः यह कहना कि आज की सारी आर्थिक समस्याओं की जड़ महिलाओं का रोजगार है, न तो न्यायसंगत है और न ही तथ्यों पर आधारित। उतना ही गलत यह कहना होगा कि आधुनिक व्यवस्था में कोई समस्या ही नहीं है। वास्तविकता इन दोनों अतियों के बीच है। परिवारों पर बढ़ता आर्थिक दबाव, बच्चों के लिए समय की कमी और सामाजिक बदलाव गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन इनके समाधान के लिए हमें व्यापक आर्थिक सुधार, परिवार समर्थक नीतियां और लैंगिक सहयोग की आवश्यकता है, न कि समाज के आधे हिस्से को समस्याओं का कारण घोषित करने की। किसी भी सभ्यता की मजबूती तब बढ़ती है जब वह अधिकार और उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और परिवार, विकास और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सके। यही संतुलन भविष्य के स्वस्थ, समृद्ध और संवेदनशील समाज की आधारशिला बनेगा।

डॉ. प्रियंका सौरभ

न्यूगल नदी और पेयजल पर बढ़ता संकट

प्रशासन और नगर निगम का उद्देश्य केवल यह साबित करना नहीं होना चाहिए कि ह्यसब ठीक हैह्न, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि हर नागरिक तक पहुंचने वाला पानी वास्तव में सुरक्षित है। उन्हें यह समझना होगा कि विकास का अर्थ केवल भवन, सडकें और परियोजनाएं नहीं होता। यदि विकास की कीमत लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा और सुरक्षित पेयजल से चुकानी पड़े, तो वह विकास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ समझौता है। न्यूगल नदी केवल पानी की धारा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जीवनरेखा है। यदि यह प्रदूषित हुई, तो उसका असर केवल नदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर उस घर तक पहुंचेगा जहां इस पानी से जीवन चलता है।

पालमपुर की पहचान उसकी हरियाली, चाय बागानों और निर्मल जलधाराओं से रही है। लेकिन आज यही पालमपुर कचरा प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक गंभीर पर्यावरणीय और जनस्वास्थ्य संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हर बरसात के साथ नगर निगम के ठोस कचरा उपचार संयंत्र की भयावह स्थिति फिर सामने आ जाती है, लेकिन समाधान आज भी दूर की बात लगता है। संयंत्र के आसपास रहने वाले लोग वर्षों से असहनीय दुर्गंध, गंदगी और संभावित स्वास्थ्य खतरों को झेल रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है, लोगों का अपने ही घरों में रहना मुश्किल हो गया है और मानसून इस समस्या को कई गुना बढ़ा देता है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह कचरा उपचार संयंत्र न्यूगल नदी के किनारे स्थित है। न्यूगल केवल एक नदी नहीं, बल्कि पालमपुर और आसपास के अनेक क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं की जीवनरेखा है। यदि कचरे से निकलने वाला विषैला तरल (लीचेट) वर्षा के पानी के साथ नदी या भूजल तक पहुंचता है, तो इसका प्रभाव केवल नदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हजारों लोगों के घरों तक पहुंचने वाले पीने के पानी पर भी पड़ सकता है। यह केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि सीधे-सीधे जनस्वास्थ्य का विषय है।

हाल ही में थुरल क्षेत्र में पीलिया (जॉन्डिस) के अनेक मामले सामने आए हैं। यह सर्वविदित है कि पीलिया प्रायः दूषित पेयजल के माध्यम से फैलता है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि पेयजल की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जाए। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या प्रशासन न्यूगल नदी और उससे जुड़ी पेयजल योजनाओं के पानी की नियमित एवं स्वतंत्र जांच करवा रहा है? यदि जांच हो रही है, तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? पारदर्शिता से बचने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है? यह चिंता इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे पर संज्ञान लिया था। नगर निगम ने स्थिति सुधारने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन वर्षों बाद भी वही शिकायतें, वही दुर्गंध और वही आश्वासन सुनाई दे रहे हैं। यदि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी हालात नहीं बदले, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर उदासीनता का प्रमाण है। आज आवश्यकता केवल कचरा हटाने की नहीं, बल्कि पूरे कचरा प्रबंधन तंत्र की वैज्ञानिक समीक्षा की है। न्यूगल नदी की जल गुणवत्ता की नियमित और स्वतंत्र जांच, लीचेट प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, संयंत्र का स्वतंत्र पर्यावरणीय ऑडिट तथा आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अधिक उपयुक्त स्थान की पहचान, इन सभी विषयों पर तत्काल और गंभीरता से काम होना चाहिए। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जनहित के इन मूलभूत प्रश्नों की जगह सत्ता और जीत के जश्न को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इंदौर की घटना पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त इंदौर में भी दूषित पेयजल के कारण सैकड़ों लोग बीमार पड़े और कई लोगों की जान चली गई। जांच में सामने आया कि सीवेज का पानी पेयजल पाइपलाइन में मिल गया था, जिसके बाद व्यापक जल गुणवत्ता परीक्षण और पाइपलाइन ऑडिट कराना पड़ा। यह घटना बताती है कि लापरवाही का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। पालमपुर की परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सबक वही है जब जल स्रोतों के निकट कचरा प्रबंधन में लापरवाही की आशंका हो, तब किसी दुर्घटना का इंतजार करना सबसे बड़ी भूल होगी। न्यूगल नदी और इससे जुड़ी सभी पेयजल योजनाओं के पानी की नियमित, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि सब कुछ सुरक्षित है तो इससे जनता का विश्वास मजबूत होगा, और यदि कोई खतरा है तो समय रहते उसे रोका जा सकेगा।

प्रशासन और नगर निगम का उद्देश्य केवल यह साबित करना नहीं होना चाहिए कि ह्यसब ठीक हैह्न, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि हर नागरिक तक पहुंचने वाला पानी वास्तव में सुरक्षित है। उन्हें यह समझना होगा कि विकास का अर्थ केवल भवन, सडकें और परियोजनाएं नहीं होता। यदि विकास की कीमत लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा और सुरक्षित पेयजल से चुकानी पड़े, तो वह विकास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ समझौता है। न्यूगल नदी केवल पानी की धारा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जीवनरेखा है। यदि यह प्रदूषित हुई, तो उसका असर केवल नदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर उस घर तक पहुंचेगा जहां इस पानी से जीवन चलता है। इसलिए अब समय आश्वासनों का नहीं, बल्कि जवाबदेह, पारदर्शी और वैज्ञानिक कार्रवाई का है। क्योंकि जब जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, तब केवल नदियां नहीं मरतीं, समाज का स्वास्थ्य, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और विकास का पूरा दावा भी प्रदूषित हो जाता है। जनकल्याण के लिए प्रदूषण को खत्म करना ही होगा।

नीलम सूद, स्वतंत्र लेखिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (एमपीएमएस) को मंजूरी दिया जाना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व का निर्णय है। 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली यह योजना केवल मोबाइल फोन निर्माण बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान, डिजाइन और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाना है।

मोबाइल फोन विनिर्माण योजनाः आत्मनिर्भर भारत से वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व की ओर एक निर्णायक कदम

यह योजना ऐसे समय में लाई गई है, जब बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए लागू उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है। नई योजना उस सफलता को अगले चरण तक ले जाने का प्रयास है। इसका कार्यकाल वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों का होगा।एमपीएमएस के अंतर्गत भारत में निर्मित मोबाइल फोन की पात्र बिक्री पर 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि निमार्ता प्रमुख पुर्जों और उप-असेंबलियों की घरेलू खरीद बढ़ाते हैं तो उन्हें 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं भारतीय ब्रांडों को डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल असेंबली आधारित उत्पादन नहीं, बल्कि वास्तविक तकनीकी क्षमता, नवाचार और बौद्धिक संपदा निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहती है।

सरकार का अनुमान है कि योजना की अवधि में देश में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन होगा। साथ ही मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर इससे कहीं अधिक होंगे, जिससे लाखों युवाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।पिछले एक दशक में ह्यमेक इन इंडियाह्न अभियान के तहत भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014-15 की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग सात गुना तथा निर्यात ग्यारह गुना बढ़ चुका है। आज भारत मात्रा के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निमार्ता है और देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन भारत में ही निर्मित हो रहे हैं।वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया, जिसने डीजल ईंधन और कटे-तराशे हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों को भी पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि दशार्ती है कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अब भारतीय अर्थव्यवस्था की नई विकास धुरी बनता जा रहा है।नई योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें भारतीय कंपनियों को अपने स्वयं के ब्रांड, डिजाइन और अनुसंधान विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।लंबे समय तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए विनिर्माण केंद्र बना रहा, लेकिन अब लक्ष्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि तकनीकी स्वावलंबन, भारतीय पेटेंट और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय ब्रांड तैयार करना है।घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने पर विशेष बल देने से मोबाइल फोन उद्योग में चिप,कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले,बैटरी,प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आपूर्ति श्रृंखला अधिक मजबूत तथा सुरक्षित बनेगी।आज वैश्विक कंपनियाँ अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं।ऐसे समय में भारत के पास कुशल मानव संसाधन,विशाल घरेलू बाजार,बेहतर अवसंरचना और अपेक्षाकृत स्थिर नीतिगत वातावरण जैसी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। एमपीएमएस इन सभी क्षमताओं को एकीकृत करते हुए भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।हालाँकि इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घरेलू अनुसंधान एवं विकास, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योग, कौशल विकास और नवाचार को समान गति से आगे बढ़ाया जाए। यदि इन क्षेत्रों में भी निरंतर और लक्षित निवेश हुआ तो भारत केवल मोबाइल फोन का निर्माण ही नहीं करेगा, बल्कि भविष्य की मोबाइल तकनीकों के विकास और निर्यात में भी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।स्पष्ट है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम केवल एक प्रोत्साहन योजना नहीं,बल्कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर, नवाचार-आधारित और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स महाशक्ति बनाने की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण आधार है।आने वाले वर्षों में यह योजना भारतीय उद्योग,रोजगार,निर्यात और तकनीकी नेतृत्व को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ, तो यह पहल भारत को केवल दुनिया का बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि दुनिया का विश्वसनीय तकनीकी निमार्ता और नवाचार केंद्र भी बना सकती है।

लेखक-विनोद कुमार सिंह तकियावाला

आलेख

महिला आरक्षण का ऐतिहासिक क्षण सामने

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जो केवल कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं होते बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नई दिशा तय करते हैं। महिला आरक्षण का प्रश्न भी ऐसा ही विषय है। वर्षों से देश की आधी आबादी संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करती रही है। अनेक सरकारें आईं और गईं। अनेक समितियां बनीं। अनेक बार विधेयक प्रस्तुत हुआ। बहसें हुईं। समर्थन और विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। लेकिन यह सपना हर बार अधूरा रह गया। अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले राजनीतिक माहौल यह संकेत दे रहा है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को वास्तविकता का रूप देने की तैयारी तेज हो चुकी है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी सकारात्मक रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के अधिकार किसी दल की राजनीति का विषय नहीं होने चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे इस ऐतिहासिक पहल में सहयोग करें ताकि वर्षों से लंबित यह सपना अब पूरा हो सके। यह परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सर्वसम्मति बनाई जाए।

महिला आरक्षण का विचार नया नहीं है। इसकी चर्चा तीन दशक से अधिक समय से होती रही है। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि अवसर मिलने पर महिलाएं नेतृत्व की नई मिसाल कायम करती हैं। लाखों महिला जनप्रतिनिधियों ने गांव और शहर के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यही अनुभव अब संसद और विधानसभाओं तक पहुंचाने का समय है।

भारत की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है लेकिन संसद और अधिकांश विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। लोकतंत्र तभी मजबूत माना जाएगा जब निर्णय लेने वाली संस्थाओं में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी हो। महिला आरक्षण इसी लोकतांत्रिक संतुलन को स्थापित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस बार राजनीतिक परिस्थितियां पहले से अलग हैं। सरकार स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण लागू करने की इच्छा जता रही है। विपक्ष का बड़ा हिस्सा भी इसका समर्थन कर रहा है। ऐसे में वर्षों से चली आ रही राजनीतिक खींचतान समाप्त होती दिखाई दे रही है। यदि सभी दल सहयोग करें तो यह विधेयक आसानी से पारित हो सकता है और भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय जुड़ सकता है।

अब प्रश्न यह भी उठता है कि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के पास लंबे समय तक सत्ता रही और कई अवसरों पर मजबूत राजनीतिक स्थिति भी थी तब महिला आरक्षण का सपना पूरा क्यों नहीं हो सका। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से स्वयं को महिला अधिकारों की समर्थक पार्टी बताती रही है।

सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य हुआ। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया गया था। लेकिन लोकसभा में इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी। इसके पीछे सहयोगी दलों के विरोध और विभिन्न राजनीतिक समीकरणों का हवाला दिया गया। कुछ दल आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग कर रहे थे जबकि कुछ अन्य दलों ने इसका खुला विरोध किया। कांग्रेस इन मतभेदों को दूर करने और आवश्यक राजनीतिक सहमति बनाने में सफल नहीं हो सकी। परिणाम यह हुआ कि विधेयक कानून नहीं बन पाया।

यही वह बिंदु है जहां कांग्रेस की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर प्रश्न उठते हैं। यदि किसी सरकार की प्राथमिकता वास्तव में किसी ऐतिहासिक सुधार को लागू करना हो तो वह व्यापक संवाद स्थापित कर राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास करती है। महिला आरक्षण के मामले में यह प्रक्रिया पूरी मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकी। कई अवसर ऐसे आए जब सरकार अधिक निर्णायक भूमिका निभा सकती थी लेकिन राजनीतिक जोखिम उठाने से परहेज किया गया। इसलिए यह कहना उचित होगा कि केवल समर्थन व्यक्त करना पर्याप्त नहीं था बल्कि अंतिम परिणाम तक पहुंचना भी आवश्यक था।

आज की परिस्थिति में विपक्ष का समर्थन स्वागत योग्य है। यदि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण के पक्ष में खड़े होते हैं तो यह देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होगा। इस विषय पर किसी प्रकार के राजनीतिक गिले शिकवे या पुराने विवादों को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। यह समय श्रेय लेने का नहीं बल्कि इतिहास बनाने का है।

महिला आरक्षण केवल महिलाओं के लिए सीटें सुरक्षित करने की व्यवस्था नहीं है। यह राजनीति की कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन का माध्यम भी बन सकता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शिक्षा स्वास्थ्य पोषण महिला सुरक्षा बाल कल्याण और सामाजिक विकास जैसे विषयों को अधिक प्राथमिकता मिलने की संभावना बढ़ेगी। विश्व के अनेक देशों का अनुभव भी यही बताता है कि महिलाओं की प्रभावी भागीदारी से लोकतांत्रिक संस्थाएं अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनती हैं।

यह भी याद रखना चाहिए कि आरक्षण का उद्देश्य किसी को विशेष लाभ देना नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करना है। समाज में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की है। विज्ञान खेल सेना न्यायपालिका प्रशासन उद्योग और अंतरिक्ष तक उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। अब राजनीति में भी समान अवसर देना समय की मांग है।

मानसून सत्र को लेकर जिस प्रकार राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं उससे उम्मीद जगी है कि इस बार केवल चर्चा नहीं होगी बल्कि ठोस परिणाम भी सामने आएगा। सरकार यदि पूरी तैयारी के साथ विधेयक लाती है और विपक्ष उसी सकारात्मक भावना के साथ सहयोग करता है तो यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा।

आज देश की करोड़ों महिलाएं इस ऐतिहासिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे केवल वादा नहीं बल्कि अधिकार चाहती हैं। वे केवल प्रतीकात्मक सम्मान नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी की भागीदारी चाहती हैं। यही लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ भी है।

अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि महिला आरक्षण का सही समय आ चुका है। तीन दशकों से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त होने की ओर है। राजनीतिक दलों ने यदि परिपक्वता का परिचय दिया और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा तो आने वाला मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। यह केवल एक कानून नहीं होगा बल्कि आधी आबादी के सम्मान समान अधिकार और सशक्त भविष्य का नया संकल्प होगा। यही वह अवसर है जब राजनीति को इतिहास रचना चाहिए और भारत को दुनिया के सामने यह संदेश देना चाहिए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी समावेशी सोच और समान भागीदारी में निहित होती है।

लेखक - कांतिलाल मांडोत

संक्षिप्त वार्ता

कांग्रेस दिल्ली में 20 जुलाई को नेकां के विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी : तारिक हमीद कर्रा

जम्मू, 17 जुलाई (वेब वार्ता)। जम्मू-कश्मीर की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 20 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) द्वारा आयोजित किये जाने वाले विरोध प्रदर्शन में उनकी पार्टी भी शामिल होगी।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीपी) अध्यक्ष कर्रा ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नेकां ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पार्टी नेतृत्व को इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के 1.4 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, भावनाओं और संवेदनाओं का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन या राजनीतिक दल इस आंदोलन से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है।

आईआरएस अधिकारी की बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत में 973 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि आरोपी घर में पहले घरेलू सहायक के तौर पर काम करता था और वित्तीय कदाचार के कारण इस साल फरवरी में उसे नौकरी से निकाला गया था। मीणा को यह पता था कि घर की चाबियां और उक्त कमरे की दूसरी चाबी कहां रखी रहती है। उसने 22 अप्रैल की सुबह इसी जानकारी का इस्तेमाल करके घर में प्रवेश किया और पीड़िता का बलात्कार किया। घटना के वक्त पीड़िता घर पर अकेली थी।सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्नातक पीड़िता को उसके माता-पिता ने सुबह करीब आठ बजे जिम से लौटने पर जख्मी पाया और उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था।

बैंक कॉलोनी को वजीराबाद रोड से जोड़ने वाले रास्ते पर बॉटलनेक होगा खत्म

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली क्षेत्र में बैंक कॉलोनी व हर्ष विहार के लोगों को वजीराबाद रोड पर आने-जाने के लिए जल्द खुला रास्ता मिलेगा। बॉटलनेक (संकरा हिस्सा)को खत्म करने के लिए 10 पेड़ हटाकर रोड को 18 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इससे लोगों को सुविधा होगी। दमकल और एंबुलेंस भी आसानी से अंदर पहुंच पाएगी।

बैंक कालोनी व हर्ष विहार मंडोली जेल के पास है। इनके वजीराबाद रोड पर आने-जाने का डेढ़ किलोमीटर से अधिक लंबा मुख्य रास्ते का ज्यादा हिस्सा 22 मीटर चौड़ा है। लेकिन 55 मीटर का हिस्सा मात्र नौ मीटर चौड़ा है।इसलिए संकरे हिस्से में जाम लगता है। जब जब लोग वजीराबाद रोड से इन कॉलोनियों में जाते और आते तो जाम मिलता है। इस छोटे से हिस्से को पार करने में 20 से 30 मिनट लग जाता है। एंबुलेंस को जाने में समस्या होती है। दमकल की गाड़ियों को भी जगह नहीं मिलने के कारण घूम कर दूसरे क्षेत्रों से जाना पड़ता है। इन कॉलोनियों के लोग कई वर्षों से संकरे हिस्से को चौड़ा करने की मांग करते आ रहे हैं। इन्होंने चुनाव में इसे मुद्दा बनाते हुए नेताओं के समक्ष इस मांग को रखा। लोगों की समस्या को देखते हुए डीडीए से सड़क को चौड़ा करने के लिए मीटर जमीन मांगी गई। डीडीए से जमीन मिलने पर अब सड़क के संकरे हिस्से को 18 मीटर चौड़ा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि सड़क के जिस हिस्से को चौड़ा करना है, वहां अलग-अलग तरह के 10 पेड़ हैं। उनको हटाने की वन विभाग से मंजूरी मिल गई है।

दिल्ली में 1,100 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने के लक्ष्य को किया जाएगा पूरा: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शकूरपुर से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली सरकार जल्द ही 1,100 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह केवल नए स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन नहीं, बल्कि राजधानी के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी नागरिक को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और लोगों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि आज के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली में 415 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर लोगों को उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों में नागरिकों को सामान्य ओपीडी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, गैर-संचारी रोगों की नि:शुल्क जांच, आवश्यक दवाइयां, स्वास्थ्य परामर्श और लगभग 80 प्रकार की नि:शुल्क जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त इन केंद्रों में बीमारी की रोकथाम, शुरूआती पहचान, समय पर उपचार और स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों के बीच स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने नागरिकों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, संतुलित जीवनशैली अपनाने और योग एवं व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने शकूरपुर कार्यक्रम के बाद त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14.25 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नेताजी सुभाष प्लेस क्षेत्र में पांच सड़कों और एक नाले के पुनर्निर्माण कार्यों की भी शुरूआत की। इसके अतिरिक्त सम्राट एन्क्लेव मार्केट के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा गुर्जर चौपाल, सैनी चौपाल एवं शकूरपुर श्मशान भूमि के विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी द्वारा 6.25 करोड़ रुपये की लागत से विकसित आठ प्रमुख सड़कों, लॉरेंस रोड, महर्षि परशुराम मार्ग, परवाना रोड, जी एवं एच शकूरपुर रोड, एकलव्य मार्ग, तिरुवल्लुवर मार्ग, वीर हेमू समेत अन्य मार्गों का भी लोकार्पण किया गया।

...आगे बढ़ सकें

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जहां प्रत्येक नागरिक को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर सड़कें और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे दिल्ली एक स्वस्थ, समृद्ध और विकसित राजधानी के रूप में आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि पहली बार राजधानी के हर विधानसभा क्षेत्र में बड़े स्तर पर सड़कों, नालों, कॉलोनियों और झुग्गी-बस्तियों में तेजी से काम हो रहा है। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र वर्षों तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझता रहा, लेकिन अब क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। जनता के वोट ने ऐसी सरकार को चुना है, जो सेवा और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस अवसर पर त्रिनगर से विधायक तिलक राम गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

दिल्ली पुलिस को नया मुखिया, अनुराग कुमार बने आयुक्त

नई दिल्ली, वेब वार्ता। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार अनुराग कुमार ने सतीश गोलचा का स्थान लिया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक वह इस पद पर बने रहेंगे। वहीं, वर्तमान पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को आगे की तैनाती के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुराग कुमार अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम तथा केंद्र शासित प्रदेश संवर्ग के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद उन्हें राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुराग कुमार लंबे समय तक आसूचना ब्यूरो में महत्वपूर्ण दायित्व निभाते रहे हैं। वह वहां विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस में उत्तर-पूर्वी जिले तथा उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद वह प्रतिनियुक्ति पर आसूचना ब्यूरो चले गए और लंबे समय तक वहीं विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे। हाल ही में उनका स्थानांतरण पुन: अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम तथा केंद्र शासित प्रदेश संवर्ग में किया गया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, सतीश गोलचा को अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने उस समय एसबीके सिंह का स्थान लिया था। 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सतीश गोलचा इससे पहले तिहाड़ कारागार के महानिदेशक तथा अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

जींद से चली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित भारत की गति, संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक है: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 17 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर समस्त हरियाणावासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व, गौरव और आत्मविश्वास का क्षण है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर अपने संदेश में कहा कि आज का दिन उनके लिए विशेष भावनात्मक महत्व रखता है, क्योंकि उनका बचपन हरियाणा के जींद में बीता है और उसी धरती से आज भारत के भविष्य की नई यात्रा शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि जींद से चली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित भारत की गति, संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत नवाचार, आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा के नए युग का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ देश के स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर विकसित भारत के संकल्प को मजबूत कर रही है।

वन महोत्सव-2026 के दौरान दिल्ली सरकार लगाएगी देशज प्रजातियों के पौधे

नई दिल्ली,वेब वार्ता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चलाए जा रहे व्यापक पौधारोपण अभियान का उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना है। इसके तहत ऐसी देशज (स्थानीय) प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं, जो वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं और जिन्हें अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। दिल्ली पुलिस द्वारा ह्यवन महोत्सव-2026 के तहत आयोजित पौधारोपण अभियान को संबोधित करते हुए सिरसा ने दावा किया कि इन देशज पौधों की जीवित रहने की दर 97 से 99 प्रतिशत है।

अरविंद केजरीवाल ने फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, वेब वार्ता। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परमवीर चक्र से सम्मानित फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सेखों का अद्भुत शौर्य, अदम्य साहस, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान आज भी देशवासियों, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपने संदेश में 1971 युद्ध में दुश्मन जहाजों के परखच्चे उड़ाने वाले, परमवीर चक्र से सम्मानित फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनके अद्भुत शौर्य, देशभक्ति और बलिदान से आज देश का बच्चा-बच्चा प्रेरित है।

उन्होंने कहा कि ऐसे वीर सपूतों का जीवन हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने की सीख देता है। उल्लेखनीय है कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना जिले के रुरका (इसेवाल) गांव में हुआ था। सेखों भारतीय वायुसेना के अब तक के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरबेस की रक्षा करते हुए उन्होंने संख्या में अधिक और आधुनिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का निर्भीकता से सामना किया। उनके पिता, तरलोचन सिंह सेखों भी भारतीय वायु सेना में वारंट ऑफिसर थे। जून 1967 में उन्हें भारतीय वायु सेना में पायलट के रूप में कमीशन किया गया था।

अरविंद केजरीवाल ने नीट-यूजी टॉपर आर्यन को दी बधाई

नई दिल्ली, 17 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीट-यूजी परीक्षा में टॉप करने वाले आर्यन को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि आर्यन ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे पंजाब का नाम रोशन किया है और वह देशभर के लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा हैं।

दिल्ली में किन्नर के भेष में रह रहा बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली पुलिस ने महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र के एनएस मंडी इलाके से एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है, जो अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए किन्नर के भेष में रह रहा था और अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर-पश्चिम जिले की पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर-पश्चिम जिले की फॉरेनर सेल को अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र के एनएस मंडी इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति छिपकर रह रहा है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में एसआई सपन, एएसआई राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल विक्रम, कांस्टेबल निशांत और कांस्टेबल दीपक बांगड़ की टीम ने छापेमारी की। मुखबिर की निशानदेही पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान वह भारत में रहने या यात्रा से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने उसके दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य जानकारियों का गहन सत्यापन किया। जांच में पुष्टि हुई कि वह बांग्लादेश का नागरिक है और बिना किसी वैध अनुमति के भारत में रह रहा था।

डूसू चुनाव के लिए सख्त नियम लागू, उल्लंघन पर नामांकन होगा रद्द

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव प्रचार के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत परिसर में मुद्रित पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स और होर्डिंग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों का नामांकन तक रद्द किया जा सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव प्रचार के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत परिसर में मुद्रित पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स और होर्डिंग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों का नामांकन तक रद्द किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार परिसर और उसके आसपास किसी भी प्रकार के मुद्रित पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स अथवा होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित लोकतंत्र दीवार पर हाथ से बनाए गए पोस्टर लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा दीवारों पर रंग छिड़कने, छपाई करने या सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम के विज्ञापन पट्टों पर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 5 वाहनों का ही उपयोग कर सकेगा। ट्रैक्टर, खुदाई मशीन, पशुओं, बिना पंजीकरण संख्या वाले वाहनों तथा काले शीशों वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार के नाम वाले चिप्पे, उपहार, छायादार तंबू, छाते अथवा अन्य प्रचार सामग्री के वितरण या प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं होगी। इन नियमों का उल्लंघन होने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सार्वजनिक सभाओं के आयोजन के लिए प्रॉक्टर कार्यालय को पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया है, ताकि परिसर में अव्यवस्था और यातायात संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। महाविद्यालयों में प्रचार के लिए एक बार में केवल 5 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा, जबकि छात्राओं के छात्रावासों में प्रचार की अनुमति केवल छात्राओं को ही होगी।

दिया आश्वासन

प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की आचार संहिता पहले से लागू है। बैठक में उपस्थित सभी छात्र संगठनों ने निर्धारित नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

वन महोत्सव-2026 के दौरान दिल्ली सरकार लगाएगी देशज प्रजातियों के पौधे : पर्यावरण मंत्री सिरसा

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चलाए जा रहे व्यापक पौधारोपण अभियान का उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना है। इसके तहत ऐसी देशज (स्थानीय) प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं, जो वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं और जिन्हें अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है।

दिल्ली पुलिस द्वारा ह्यवन महोत्सव-2026ह्ल के तहत आयोजित पौधारोपण अभियान को संबोधित करते हुए सिरसा ने दावा किया कि इन देशज पौधों की जीवित रहने की दर 97 से 99 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पौधे पर ह्यटैगह्ल लगाया जाएगा और हर पौधारोपण स्थल का ह्यजियोटैगह्ल किया जाएगा। जियोटैग में जहां-जहां पौधे लगाए जाएंगे, उन सभी स्थानों का सटीक लोकेशन डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे अधिकारी मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से यह देख सकेंगे कि पौधे कहां लगाए गए हैं और उनकी स्थिति क्या है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष दिल्ली में लगभग 70 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिनमें से 15 लाख पौधे दिल्ली रिज क्षेत्र में लगाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि यह कार्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की परिकल्पना पर आधारित 10 वर्षीय हरित मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है। सिरसा ने कहा, दिल्ली रिज में पौधारोपण योजना का उद्देश्य देशज प्रजातियों के पेड़ों के माध्यम से वन क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। ये पेड़ स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं, प्रदूषण कम करने में सहायक हैं और इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और सरकार जहां भी भूमि उपलब्ध है, वहां पौधारोपण अभियान चलाकर हरित क्षेत्र का अधिकतम विस्तार करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, पारंपरिक पौधारोपण के अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में मियावाकी वन भी विकसित किए जा रहे हैं।

मियावाकी पद्धति को वृक्षारोपण की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक माना जाता है, जिसके माध्यम से अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा चुकी या क्षतिग्रस्त भूमि पर कम समय में घना वन विकसित किया जा सकता है। इस पद्धति का विकास जापानी वनस्पति वैज्ञानिक डॉ. अकीरा मियावाकी ने किया था। सरकार के अपशिष्ट प्रबंधन प्रयासों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगभग 202 एकड़ क्षेत्र में कचरे के पुराने ढेर मौजूद हैं, जिनमें से पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान कई एकड़ भूमि को कचरा मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस पुनः प्राप्त भूमि पर भी पौधारोपण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के इस व्यापक पौधारोपण अभियान में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा सहित पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

दिल्ली के कंझावला में एसयूवी से कई बार कुचले जाने से स्कूटर सवार की मौत

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली के कंझावला इलाके में एक एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) द्वारा कथित तौर पर कई बार कुचले जाने के बाद 38 वर्षीय एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना चांदपुर गांव के पास हुई। उसने बताया कि हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस एसयूवी और उसके चालक की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि यह एक सोची-समझी हत्या है। परिजनों का दावा है कि पीड़ित पर इससे पहले भी दो बार हमला किया गया था लेकिन वह बच गया था। पुलिस ने कहा कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

शामली व कैराना की डेमोग्राफी बदल रहे थे जिन्ना के उपासक: मुख्यमंत्री

वेब वार्ता, कैराना/शामली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिन्ना के उपासक लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे और इसीलिए कैराना व कांधला से पलायन हो रहा था। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को चेताया कि जिन्ना के अनुयायियों को जब भी मौका मिलेगा, वे आपको क्षेत्र व जाति के नाम पर बांटेंगे। विकास कार्यों में लूट-खसोट करेंगे। बेटी-व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएंगे। इनसे लगातार सतर्क रहना है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को कैराना, शामली व थानाभवन विधानसभा क्षेत्र की 581 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण व शिलान्यास की गई योजनाओं का विवरण देते हुए गत 10 वर्ष में शामली, थानाभवन व कैराना में आए सकारात्मक बदलाव की भी चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध में जाने से पहले लीलाधारी प्रभु श्रीकृष्ण ने हनुमान टीले में आकर विश्राम किया था और यहां के पवित्र जल को ग्रहण किया था। शामली व कैराना ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिला दिया था। कैराना घराने से पं. भीमसेन जोशी ने शास्त्रीय संगीत की परंपरा को नई ऊंचाई दी। सीएम ने कहा कि 10 साल पहले लोग पूछते थे कि आतंक-भय का प्रतीक शामली जनपद कहां है। शामली, कैराना-कांधला से पलायन होता था, यहां गुंडागर्दी होती थी। कोई सुरक्षित नहीं था। शरारत के तहत डेमोग्राफी को बदलने की साजिश हो रही थी। अब यहां के गन्ने की मिठास प्रसिद्ध है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार शामली की गति को प्रगति में बदल रही है।

एक्सप्रेसवे का 'संगम' बन चुका है शामली

मुख्यमंत्री ने कहा कि शामली अब दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली-अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे का 'संगम' बन चुका है। यहां की युवा पीढ़ी की ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में किया गया तो आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर व सुरक्षा का यह बेहतर माहौल शामली को एनसीआर के सबसे धनी व समृद्ध जनपदों में खड़ा कर देगा। शामली वाले 10 साल पहले बिजली के लिए तरसते थे, लेकिन आज शामली 400 केवीए विद्युत स्टेशन के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति का माध्यम बना है। 10 साल पहले मेडिकल सुविधाएं नदारद थीं। लेकिन, कोरोना महामारी में दिल्ली व आसपास के लोग इलाज कराने शामली के हॉस्पिटलों में पहुंचे।

सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों चौधरी जयंत सिंह, वीरेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा के कार्यों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में चौधरी चरण सिंह के बाद चीनी मिलों की स्थिति में सुधार व पुनरोद्धार का बीड़ा 2017 में सुरेश राणा ने उठाया था। 2007 से 2017 के बीच तत्कालीन सरकारों में 29 चीनी मिलें बंद हुईं। 21 मिलें औने-पौने दाम पर बेची गईं। 2017 में सुरेश राणा ने मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली तो मैंने पूछा कि अब मिलें बिकेंगी तो नहीं, तब उन्होंने कहा था कि इन मिलों को वापस लेकर चलाएंगे। आज 122 चीनी मिलें चल रही हैं और किसानों को समय से भुगतान हो रहा है। अब गन्ना किसानों को 400 रुपये कुंतल दाम मिल रहा है। यूपी चीनी, गन्ना व एथेनॉल उत्पादन में नंबर एक है। यह प्रगति किसानों की समृद्धि का कारक बनी है। सीएम योगी ने कहा कि विकास का विकल्प नहीं हो सकता। हम किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया। हमने भी चीनी मिलों के माध्यम से उन्हें गन्ना मूल्य का भुगतान करा के दिखा दिया। शामली की खुशहाली और थानाभवन-कैराना का विकास देख लगता है कि सार्वजनिक जीवन में आना सफल हुआ है। पिछली बार मैंने यहां के स्कूलों का दौरा किया था। यूपी-सीबीएसई बोर्ड की मेरिट सूची में शामली के बच्चों का नाम देखा तो उन्हें लखनऊ बुलाया। वे बच्चे भी बता रहे थे कि अब डर नहीं लगता, क्योंकि अपराधी जानता है कि हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में ही जगह मिलेगी। सीएम ने कहा कि शामली में तेज गति से प्रगति होगी। कैराना में पीएसी की भव्य बटालियन बन रही है। सैफई का नौकरी का सिंडिकेट अब शामली के युवाओं का अधिकार नहीं छीन सकता।

कई जिलों में गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

प्रयागराज, वेब वार्ता। मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ ने शुक्रवार सुबह प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार शुक्रवार को प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, झांसी, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, हरदोई, फरुर्खाबाद, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत सहित आसपास के क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। किसानों को भी मौसम को देखते हुए कृषि कार्यों में आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

संक्षिप्त वार्ता

ब्राह्मण समाज का गौरव ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने नीट में हासिल की शानदार सफलता

वेब वार्ता, कमर खान

पचपेड़वा / बलरामपुर। क्षेत्र के अचकवापुर निवासी ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने ठएएळ (टइइर) परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 573 अंक प्राप्त किए हैं। इस शानदार सफलता के साथ उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग में लगभग 1,75,000 अभ्यर्थियों के बीच 19,000 वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार, समाज और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

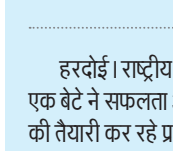

ज्ञान प्रकाश मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा के छोटे भाई हैं, जिनकी इस उपलब्धि से पूरे गैसड़ी व बलरामपुर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। उनकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि समर्पण और निरंतर प्रयास से बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी इस उपलब्धि पर ब्राह्मण समाज सहित समस्त क्षेत्रवासियों ने गर्व व्यक्त किया है और उन्हें बधाई दी है। परिवार के सदस्यों ने उनकी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

बलिया में रीडिंग महोत्सव, सनबीम स्कूल में विद्यार्थियों ने एक साथ पढ़ी किताबें

वेब वार्ता,(वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया सनबीम स्कूल के परिसर में शुक्रवार को रीडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में उपस्थित हर विद्यार्थी के हाथ में पुस्तकें नजर आईं। सनबीम स्कूल में प्रत्येक वर्ष 13 जुलाई से 25 जुलाई तक विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने और पढ़ने के महत्व से रूबरू कराने के उद्देश्य से रीडिंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के एक घंटे की अवधि निर्धारित थी, जिसमें सभी ने अपनी रुचि के अनुसार कहानी, कविता आदि का पाठ किया। सत्र के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर काल के दौरान बच्चों ने पढ़ी गई कहानियों और उनके पात्रों के संबंध में अत्यंत सटीक उत्तर दिए। विद्यालय निदेशक डॉ. कुंवर अरुण सिंह विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुस्तकें पढ़ने से आँखों को जो सुकून और मानसिक शांति मिलती है, वह किसी भी डिजिटल स्क्रीन से संभव नहीं है। इस अवसर पर विद्यालय के सचिव श्रीवत्स सिंह, उपप्रधानाचार्य पंकज सिंह, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर सहर बानो, हेडमिस्ट्रेस नीतू पांडेय, समन्वयक जयप्रकाश यादव, प्रशांत उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।

नीट परीक्षा में चमके कछौना के सितारे, तीन बेटियों और एक बेटे ने क्रैक किया एग्जाम

वेब वार्ता,लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट में कछौना क्षेत्र की तीन बेटियों व एक बेटे ने सफलता अर्जित कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। जिससे नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के उत्साह में इजाफा हुआ।विकासखंड कछौना के ग्राम सभा बालामऊ निवासी मनोज कुमार सिंह एल०टी० टेक्नीशियन की भतीजी निशि पटेल पुत्री पवन कुमार उम्र 19 वर्ष ने नीट की परीक्षा में सफलता अर्जित की। इंटर की परीक्षा एल.पी.एस. लखनऊ से की। उसके बाद मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए कठिन तैयारी कर मेडिकल पृष्ठभूमि के चलते निशि पटेल ने मेडिकल क्षेत्र में जाने का लक्ष्य बनाया। पिता पवन कुमार लैब टेक्नीशियन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसा में तैनात है। निशि की रैंक ऑल इंडिया 28800 हैं। ओबीसी वर्ग के तहत 13000 है, नंबर 561 है। सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की रास्ता खुल गई है। कछौना के हथौड़ा निवासी पत्रकार राम शंकर आजाद की पुत्रीजान्हवी आजाद ने पहले प्रयास में नीट की परीक्षा उज्जैन की ऑल इंडिया कैटेगरी में 7700वीं रैंक प्राप्त की।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गोहाना पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

गोहाना/। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन के गोहाना रेलवे स्टेशन पहुंचने पर ऐतिहासिक एवं उत्साहपूर्ण अंदाज में गोहानावासियों ने स्वागत किया गया। इस अवसर पर सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा की धर्मपत्नी डॉ रीटा शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नागरिकों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकताओं ने ट्रेन का भव्य स्वागत किया।

मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा की धर्मपत्नी डॉ रीटा शर्मा ने कहा कि हरियाणा को ऐतिहासिक सौगात मिली है जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश निरंतर आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच और हरित ऊर्जा की दिशा में नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन इसका जीवंत उदाहरण है, जो भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती से इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरूआत होना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यह केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ रीटा शर्मा ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य के स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन की पहचान बनेगी। हाइड्रोजन ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था आने वाले समय में प्रदूषण मुक्त भारत की मजबूत नींव बनेगी। यह ट्रेन डीजल एवं पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुंबई से गुवाहाटी जा रहे डीसीएम की वाराणसी में भारी ट्रक से टक्कर

वाराणसी, 17 जुलाई (वेब वार्ता)। वाराणसी में शुक्रवार को मिजार्मुराद थाना क्षेत्र के मेंहदीगंज में बड़ा हादसा हो गया। मुंबई से गुवाहाटी जा रहे डीसीएम की मेंहदीगंज में रोड पर खड़ी एक भारी ट्रक से टकरा गई। जिससे डीसीएम का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक बुरी तरह जख्मी होकर वही फंस गया। घटना के बाद भारी ट्रक वहां से निकल गई। दुर्घटना में डीसीएम चालक के फंसे होने की सूचना पर पहुंची मिजार्मुराद थाना की पुलिस टीम ने केबिन को कटर से काटकर चालक को बाहर निकाला, किंतु तब तक चालक ने दम तोड़ दिया था।

दिशा समिति की बैठक में सांसद जय प्रकाश रावत ने अधिकारियों को लगाई फटकार

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में सांसद जय प्रकाश रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और जनसमस्याओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ईसीसी एजुकेटर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए।

बैठक में सांसद जय प्रकाश रावत ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेकर उनका शीघ्र समाधान किया जाए और संबंधित जनप्रतिनिधियों को भी कार्रवाई से अवगत कराया जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग को नियमित सैंपलिंग अभियान चलाकर मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को खराब ट्रांसफार्मर तत्काल बदलने, निर्बाध बिजली आपूर्ति और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जल निगम को पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों का शीघ्र रिस्टोरेशन कराने तथा जलापूर्ति और लीकेज संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा गया। सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने, किसानों को निर्धारित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराने तथा ओवररेटिंग करने वालों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। सांसद ने सिंचाई बंधु की बैठकें नियमित कराने, पर्यटन परियोजनाओं पर शिलापट लगाने और समाज कल्याण विभाग को पेंशन संबंधी मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में आबकारी, नगर निकाय, पंचायतीराज, आवास एवं वन विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने जनपद में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की और समिति के सुझावों व निदेशों का प्रभावी अनुपालन कराने का भरोसा दिलाया। बैठक में विधायक साण्डी प्रभाष कुमार वर्मा, विधायक सण्डीला अलका सिंह अर्कवंशी, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी नेहा व्याडवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नीट 2026: आकाश के 36 छात्रों को मिली सफलता... अन्वेषा तिवारी रहीं अलीगढ़ टॉपर

वेब वार्ता, अलीगढ़। नीट यूजी 2026 परीक्षा में आकाश इंस्टीट्यूट के 36 छात्रों को सफलता मिली है। जिनमें छात्रा अन्वेषा तिवारी ऑल इंडिया रैंक 499 हासिल कर अलीगढ़ टॉपर बनी हैं। छात्रा अन्वेषा तिवारी ने अपनी इस सफलता पर शिक्षकों के मार्गदर्शन, खुद की रणनीति और परिवार के द्वारा प्रेरित करना बताया है।

इस मौके पर आकाश एजूकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के रीजनल डायरेक्टर डीके मिश्रा ने नीट यूजी 2026 में अन्वेषा तिवारी सहित सभी 36 छात्र और छात्राओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि एईएसएल का प्रयास रहा है कि छात्रों को मजबूत शैक्षणिक आधार, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने बताया कि नीट

2026 के परिणामों में अन्वेषा तिवारी ने 720 में से 670 अंक, जबकि तुषार गर्ग ने 649 अंक के साथ 1499 एआईआर, अर्पण अग्रवाल ने 648 अंक के साथ 1591 एआईआर, भाव्या सक्सेना ने 609 अंक के साथ 7435 एआईआर तथा प्रांजल शेखर ने 606 अंक प्राप्त कर 8285 एआईआर हासिल की है।

उन्होंने बताया कि एनटीए द्वारा जारी टॉप 138 की सूची के अनुसार, उत्तर प्रदेश में आकाश के छात्रों ने नीट यूजी 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। छात्र आर्यन दुबे ने स्टेट रैंक 1, वंशम सिंह ने स्टेट रैंक 3, एकाग्र यादव ने स्टेट रैंक 5, श्रीनारायण हरि मिश्रा ने स्टेट रैंक 6, अरिमा झा ने स्टेट रैंक 7 तथा कृष्णा यादव ने स्टेट रैंक 8 हासिल कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है। जबकि आकाश के 4 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप 10, 18 छात्रों ने टॉप 50 तथा 41 छात्रों ने टॉप 100 में स्थान बनाया है।

यह उपलब्धि संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी फैकल्टी, वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति, व्यापक अध्ययन सामग्री, नियमित टेस्ट और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की मजबूत व्यवस्था को दर्शाती है। इस मौके पर आकाश इंस्टीट्यूट के ब्रांच हैड अंशुल उपाध्याय, एबीएम दिव्यांशु शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर रौशन सिंह, एकेडमिक हैड गोविंद दीक्षित, पंकज यादव, शशिकांत सिंह आदि ने टॉपर छात्रों को सम्मानित किया।

छात्रों से भरी स्कूली बस पुलिया पर लटकी, बाल-बाल बचे बच्चे

महोबा, 17 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश में महोबा जनपद के महोबकंठ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह चालक की लापरवाही से स्कूली बच्चों से भरी बस पुलिया में जाकर हवा में लटक गई। बस में सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। महोबकंठ में स्थित वसंत वैली पब्लिक स्कूल की बस सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बस में लगभग 40 छात्र-छात्राएं सवार थे। बस में सवार स्कूल के छात्र रिजवान ने बताया कि बस चालक पीछे छूटे एक बच्चे को लेने के लिए बस खड़ी कर खुद ही उसे लेने चला गया। नीचे उतरने के दौरान चालक भूलवश हैंड ब्रेक न लगाए जाने के कारण बस पीछे की ओर खिसककर नाला में बनी पुलिया में हवा में लटक गई।

नीट में 561 अंक हासिल कर निशी पटेल ने बढ़ाया हरदोई का मान

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। हरदोई जिले के बालामऊ की होनहार छात्रा निशी पटेल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (ठएएळ) में 561 अंक प्राप्त कर एमबीबीएस में प्रवेश का रास्ता तय कर लिया है। उनकी इस सफलता से परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। निशी पटेल, संडीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन मनोज कुमार सिंह की भतीजी तथा पवन कुमार पटेल की पुत्री हैं। वर्तमान में वह लखनऊ में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। कठिन मानी जाने वाली इस परीक्षा में सफलता हासिल कर उन्होंने हरदोई जिले, अपने गांव बालामऊ और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। परिवार के लिए यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले मनोज कुमार सिंह की पुत्री डॉ. शैल्जा सिंह का भी एमबीबीएस में चयन हुआ था और वह अब चिकित्सक बन चुकी हैं। लगातार दूसरी पीढ़ी की इस सफलता को क्षेत्र के लोग प्रेरणादायक उपलब्धि मान रहे हैं। निशी की सफलता की सूचना मिलते ही परिजनों के पास बधाई संदेशों और फोन कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। ग्रामीणों, शुभचिंतकों और मित्रों ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। लोगों ने विश्वास जताया कि एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉ. निशी पटेल के रूप में वह समाज की सेवा करते हुए क्षेत्र का नाम और ऊंचा करेंगी।

विश्व सर्पदंश दिवस पर कार्यशाला का हुआ आयोजन

वेब वार्ता, कानपुर। पीपीएन महाविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग एवं आई.पी.आर. सेल के तत्वावधान में सर्पदंश पर कार्यशाला एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ प्राचार्य प्रो० अनूप कुमार सिंह द्वारा किया गया। डॉ० नीरज वर्मा द्वारा सर्पदंश पर व्याख्यान दिया गया जिसमें विष एवं विषहीन सर्पों के सामान्य लक्षण के बारे में बताया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने पर्यावरण सुरक्षा एवं विश्व सर्पदंश दिवस के अवसर पर छात्र एवं छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। विभिन्न माडलों के माध्यम से डॉ. बी.बी. विश्वास, डॉ. एस.पी. श्रीवास्तव, डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह, डॉ. सध्या पाण्डेय एवं डॉ. दिव्या मिश्रा ने छात्र एवं छात्राओं

को विशेष जानकारी प्रदान की। इस आयोजन में प्रो. डी. सी. कटियार, प्रो. सुशील शुक्ला, प्रो. निधि श्रीवास्तव, आई.पी.आर. कमेटी के सदस्य डॉ. यशवीर गौतम, डॉ० अनूप सिंह, डॉ. अनूप गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

बेसमेंट की खुदाई बनी आफत, पूर्व जनसंघ विधायक राजेंद्र सिंह के पुत्र के मकान की दीवार ढही

मिट्टी धंसने से आसपास के मकानों पर भी मंडराया खतरा, लोगों ने सुरक्षा मानकों पर उठाए सवाल

वेबवार्ता/हरदोई। शहर के लखनऊ रोड स्थित शर्मा मेडिकल स्टोर के सामने निमार्णाधीन भवन में बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया। खुदाई के कारण जनसंघ के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र शौर्यवर्धन सिंह चौहान के मकान की दीवार भरभराकर बेसमेंट में जा गिरी। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक निमार्णाधीन भवन में बेसमेंट के लिए गहरी खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान पड़ोसी मकान की एक दीवार अचानक ढहकर बेसमेंट में समा गई। दीवार गिरने के बाद भी लगातार मिट्टी धंसती रही, जिससे मकान के अन्य हिस्सों और छत पर भी खतरा बना हुआ है। आसपास के लोग एहतियातन मौके पर जुट गए और स्थिति का जायजा लेते रहे।

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बेसमेंट की खुदाई कराई जा रही है। इससे आसपास के मकानों की नींव कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने की नींव के नीचे से मिट्टी खिसक गई, जिससे शौर्यवर्धन सिंह चौहान के मकान आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की जांच कराने, बेसमेंट की खुदाई में निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आसपास के अन्य मकान भी खतरे की जद में आ सकते हैं।

कछौना में भूजल सप्ताह पर जागरूकता गोष्ठी

वेबवार्ता/हरदोई। भूजल सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को विकास खंड कछौना के सभागार में भूजल संरक्षण एवं जल संवर्धन विषय पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा ग्रामीणों ने भाग लिया।

खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र ने कहा कि जल प्रकृति का अमूल्य वरदान है, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से जल संरक्षण की आदत अपनानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के

लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रह सके।

लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता अशोक पाल ने कहा कि जल सभी जीव-जंतुओं और फसलों के जीवन का आधार है। उन्होंने बताया कि जल के बिना किसी भी बीज का अंकुरण संभव नहीं है। शुद्ध पेयजल की कमी के कारण लोग अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इसलिए जल संसाधनों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और जल संरक्षण संबंधी सुझावों का पालन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र, लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता अशोक पाल, प्रधान ओमप्रकाश गौतम, आशीष कुमार, महेश गुप्ता, टी.ए. राजकुमार दीक्षित, संजय कुमार, बृजेश कुमार, जयप्रकाश सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

महत्वपूर्ण ख़बर

मुर्शिदाबाद में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 छात्रों सहित 3 लोगों की मौत

- मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 2 स्कूली छात्र थे. दरअसल, बच्चों को स्कूल लेकर जा रही एक स्कूल वैन की ट्रेन से टक्कर हो गई. हादसे में कई छात्र घायल हो गए हैं. कहा जा रहा है कि घटना सुबह 7 बजे की है. एक्सीडेंट के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घटना मुर्शिदाबाद जिले के बरहमपुर की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है. पुलिस-प्रशासन की ओर से अब तक हादसे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. कहा जा रहा है कि वैन छात्रों को घरों से स्कूल ले जा रही थी. मौके पर मौजूद लोगों ने यानी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई थी और जैसे ही स्कूल वैन उसे पार करने वाली थी, तभी अचानक से निमटिता-कटवा पैसेंजर ट्रेन आई और उसने वैन को टक्कर मार दी.

पाक सेना पर बलोच आर्मी का बड़ा हमला, एक बस को उड़ाया

- मस्तुंग। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर खतरा मंडरा रहा है. यहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसके लड़ाकों ने मस्तुंग जिले के खड़कोचा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा अटैक किया है. संगठन के अनुसार, इस हमले में 45 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल हो गए. BLA के प्रवक्ता जीयंद बलोच की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस हमले को संगठन की "फतह स्क्वाड" ने अंजाम दिया. ऐसा दावा है कि निशाने पर पाकिस्तान सेना के जवानों को ले जा रही बस को उड़ा दिया गया है.

मोरिंगा के उत्पादों की बिक्री पर ऑस्ट्रेलिया ने लगाई रोक

नई दिल्ली। भारत में जिस मोरिंगा (सहजन) को ट्री ऑफ लाइफ और मिरेकल ट्री जैसे नामों से जाना जाता है, उसी मोरिंगा के पत्तों, पाउडर, तेल और कैप्सूल जैसे उत्पादों की बिक्री पर ऑस्ट्रेलिया ने रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया की खाद्य मानक संस्था ने इसे ह्यनॉवेल फूडह्ल श्रेणी में रखते हुए कहा है कि इसके खाद्य उपयोग को लेकर पर्याप्त सुरक्षा संबंधी वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में बिना मंजूरी इसके उत्पाद बेचने पर भारी जुमार्ना या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारत में मोरिंगा का उपयोग सदियों से भोजन और आयुर्वेदिक चिकित्सा दोनों में किया जाता रहा है। इसके पत्ते, फलियां, फूल और बीज पोषक तत्वों से भरपूर माने जाते हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों, विशेषकर केरल और तमिलनाडु में सहजन की सब्जी और अन्य व्यंजन दैनिक भोजन का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले अपने भोजन में मोरिंगा के पराठे और चाय को शामिल करने की बात कर चुके हैं, जिसके बाद यह पौधा स्वास्थ्यवर्धक आहार के रूप में और अधिक चर्चा में आया। विशेषज्ञों के अनुसार मोरिंगा में विटामिन, खनिज, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

आयुर्वेद में इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, सूजन कम करने, रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने और पोषण की कमी दूर करने में उपयोगी माना जाता है। वर्तमान में दुनिया के कई देशों में मोरिंगा पाउडर और अन्य उत्पाद हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में भी लोकप्रिय हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि मोरिंगा को खाद्य पदार्थ के रूप में व्यापक स्वीकृति देने से पहले इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर और वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हैं। इसी आधार पर ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड और कुछ अन्य देशों में भी इसे नॉवेल फूड की श्रेणी में रखा गया है। इसके चलते वहां बिना नियामकीय मंजूरी मोरिंगा उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। यहां तक कि सीमा पर ऐसे उत्पाद लाने पर भी उन्हें जब्त किया जा सकता है।

इस फैसले से मोरिंगा की खेती करने वाले किसानों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पारंपरिक खाद्य पदार्थों को प्रतिबंधित करने के बजाय उन पर व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने चाहिए। उनका तर्क है कि भारत, अफ्रीका, फिलीपींस और लैटिन अमेरिका सहित अनेक देशों में लोग सदियों से मोरिंगा का सेवन करते आ रहे हैं और इसे सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन माना जाता है। दूसरी ओर भारत में सरकार किसानों को मोरिंगा की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है और कई स्टार्टअप इसके आधार पर चाय, पाउडर, बिस्किट तथा अन्य स्वास्थ्य उत्पाद तैयार कर रहे हैं।

ट्रेन के एसी को कोच से चादर, कंबल, तकिया, तौलिया की हो रही चोरी

चोरी गए सामान की कीमत करोड़ों में, पकड़े जाने पर है जेल व जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय ट्रेन में रोज लाखों लोग सफर करते हैं। जनरल से लेकर एसी कोच तक यात्री अपनी मंजिल तक जाते हैं। एसी कोच में यात्रियों को चादर, कंबल, तकिया, तौलिया दिया जाता है।

हाल ही में इन चीजों की चोरी की घटना सामने आई है। चोरी किए गए सामानों की कीमत करोड़ों में है। चोरी और किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि यात्रियों ने की है, जिनकी सुविधा के लिए इन्हें दिया जाता है। इसके लिए सजा का भी प्रावधान है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चार सालों में एक करोड़ 27 लाख कीमत के रेलवे के बेडरोल्स गायब हो चुके हैं। यह आंकड़ा कोरोना महामारी के बाद जनवरी 2022 से लेकर मई 2026 तक का है। रात में यात्रियों को दी जाने वाली लिनेन सामग्री के लगातार गायब होने के बीच आरटीआई लगाने के बाद यह जानकारी सामने आई है। यह मामला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक भी पहुंचा, जिन्होंने रेलवे के सीनियर अधिकारियों को समाधान के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। रेलवे का आंकड़ा बताता है कि भारत में हर रोज रात का सफर रेलवे में करने वाले पैसेंजर्स की संख्या करीब 8 लाख होती है। लिनेन बेडरोल में सामान्य तौर पर दो सफेद चादर, एक कंबल, एक तकिया और तकिए का कवर, फेस टॉवेल दिया जाता है। रेलवे के सभी 16 जोन के मंडलों से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई तो पता चला कि कोरोना के बाद के चार सालों में बेडरोल चोरी की घटनाओं में 56 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई। इसकी वजह से ठेकेदारों को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा है।

बता दें बेडशीट, कंबल, तौलिया, तकिया को अपने साथ ले जाना करना गैरकानूनी है। इसके लिए जुमार्ने से लेकर जेल भी हो सकती है। ये सभी चीजें रेलवे की प्रॉपर्टी है। इन्हें आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, जिसको यूज के बाद वहीं छोड़ना होता है। फिर कोच का अटेंडेंट उन्हें कलेक्ट कर लेता है। कई यात्री अक्सर जर्नी खत्म होने के बाद भी इन्हें अपने साथ लगेज में भरकर लेते जाते हैं।

रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत पहली बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर एक साल तक जेल या 1000 रुपए तक का जुमार्ना हो सकता है। यह मामला अगर गंभीर हुआ तो 5 साल तक की जेल या फिर भारी जुमार्ना लगेगा। चोरी पर दोनों ऐक्शन भी लिए जा सकते हैं। रेलवे में चोरी को लेकर आरटीआई में यह आंकड़ा वस्तु और मंडल के हिसाब से भी आया है जितने फेस टॉवल चोरी हुए, उनकी कीमत 46 लाख 54 हजार, बेडशीट 41 लाख 13 हजार, कंबल 12 लाख 95 हजार, तकिए 2 लाख 76 हजार, तकिए के कवर 23 लाख 59 हजार की कीमत के चोरी हुए। रेलवे के अलग-अलग मंडल दानापुर, जोधपुर, रांची, धनबाद में सबसे ज्यादा सामानों की चोरी हुई है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर जैसे मंडलों में भी चोरी दर्ज की गई है।

ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका-चीन आमने-सामने, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित

वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक शक्तियों अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को तेज कर दी है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं और ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात गंभीर जरूर हैं, लेकिन इन्हें फिलहाल तीसरे विश्व युद्ध की शुरूआत कहना जल्दबाजी होगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लंबे समय से खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है और उसका कहना है कि वह समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा तथा अपने सहयोगी देशों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर चीन पश्चिम एशिया से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है और क्षेत्र में स्थिरता को अपनी ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक हितों के लिए बेहद अहम मानता है। यही कारण है कि दोनों महाशक्तियां इस संकट पर अलग-अलग रणनीतियां अपनाती नजर आ रही हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक चीन अब पश्चिम एशिया में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक भूमिका लगातार बढ़ा रहा है। ईरान के साथ उसके दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग समझौते और ऊर्जा संबंध इस क्षेत्र में उसकी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करते हैं। वहीं अमेरिका के सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और अन्य सहयोगी देशों के साथ लंबे समय से सुरक्षा संबंध हैं। इस कारण दोनों देशों के हित कई मामलों में एक-दूसरे से टकराते दिखाई देते हैं, हालांकि दोनों ही खुली सैन्य भिड़ंत से बचने की कोशिश करते रहे हैं।

रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि वर्तमान स्थिति को अमेरिका और चीन के बीच प्रत्यक्ष युद्ध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और किसी बड़े युद्ध की कीमत दोनों को भारी पड़ सकती है। इसलिए कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य तैनाती और क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से प्रभाव बढ़ाने की रणनीति अधिक संभावित मानी जा रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि खाड़ी क्षेत्र में जारी संकट निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए गंभीर चुनौती है, लेकिन इसके विश्व युद्ध में बदलने की संभावना सीमित है। यदि क्षेत्रीय संघर्ष नियंत्रण से बाहर होता है और कई देशों की सेनाएं सीधे इसमें शामिल हो जाती हैं, तभी व्यापक वैश्विक टकराव का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी हैं, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष का असर ऊर्जा बाजार, वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर दूरगामी हो सकता है।

अखिलेश की रथ यात्रा: 36 साल बाद धार्मिक स्थलों से भाजपा को घेरने की तैयारी?

लखनऊ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इन्हीं चुनाव तैयारी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक बड़ी राजनीतिक कवायद की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार, अखिलेश सितंबर 2026 में समाजवादी पीडीए रथ यात्रा शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। यह यात्रा 25 सितंबर, 1990 को राम मंदिर आंदोलन के लिए निकाली गई चर्चित रथ यात्रा के 36 साल पुराने इतिहास को दोहराने जैसा होगा। माना जा रहा है कि अखिलेश की यह रथ यात्रा सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है।

यात्रा की शुरूआत किसी प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल करने की चर्चा

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यात्रा की शुरूआत किसी प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल से किए जाने पर मंथन चल रहा है, जिसमें अयोध्या, मथुरा या काशी जैसे स्थानों पर विचार हो रहा है। सपा की रणनीति भाजपा को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर राजनीतिक रूप से घेरने की हो सकती है, हालांकि पार्टी नेतृत्व अभी अंतिम स्थान और तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह यात्रा समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) समीकरण को साधने पर केंद्रित होगी। समाजवादी पार्टी के इन दावों के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा से संबंधित हालिया बयान चर्चा में है। कुशीनगर में जनसभा के दौरान, मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला कर कहा था कि जो लोग युवाओं का रोजगार छीनते थे, वे अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाती थी और मंदिरों पर कब्जा करवाती थी, जबकि भाजपा सरकार उन्हीं मंदिरों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण कर रही है।

हाथी ने 2 को कुचला फिर परिवार के दो सदस्यों को 14 साल बाद मार डाला

काठमांडु। हाथियों को दुनिया के सबसे बुद्धिमान और बेजोड़ यादाश्त वाले जानवरों में गिना जाता है और नेपाल से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर उनकी स्मरण शक्ति को गहरी चर्चा में ला दिया है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान के आसपास रहने वाले एक परिवार पर एक कुख्यात जंगली हाथी ने 14 वर्ष बाद दोबारा जानलेवा हमला कर दिया, जहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी हाथी ने वर्ष 2012 में भी इसी परिवार के दो सदस्यों की जान ले ली थी। उस समय पीड़ित परिवार ने इस खौफनाक खतरे से बचने के लिए अपना पुराना घर छोड़ दिया था और कई किलोमीटर दूर दूसरी जगह जाकर बस गया था, लेकिन प्रतिशोधी हाथी सालों बाद वहां भी पहुंच गया। चितवन राष्ट्रीय उद्यान के सूचना एवं संरक्षण अधिकारी अबिनाश थापा ने इस खौफनाक घटना की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि हमलावर जंगली हाथी धुरबे पर पैनी निगरानी रखने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग कॉलर लगाया गया है और घटना के समय उसकी लोकेशन पीड़ित परिवार के नए घर के बिल्कुल आसपास ही दर्ज हुई थी, जहां अधिकारियों के अनुसार यह आदमखोर हाथी अब तक 25 निर्दोष लोगों की जान ले चुका है, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान के दो कर्मचारी भी शामिल हैं। पीड़ित शनिचारा ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि वर्ष 2012 में बोते माडी क्षेत्र में धुरबे ने उनके माता-पिता बुधिराम और झरली को बेरहमी से कुचलकर मार डाला था, जिसके बाद परिवार ने सुरक्षा के मद्देनजर रेउ और राप्ती नदियां पार कर जगतपुर में एक नया घर बना लिया था क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि हाथी इतनी दूर नदियों को पार कर वहां तक कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाल ही में धुरबे ने उनके इस नए घर में भी घुसकर उनकी बहू आशिका और महज चार वर्षीय पोते भरत की जान ले ली।

नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप पर मरना और जन्म लेना है अपराध

ओस्लो। नॉर्वे का स्वालबार्ड द्वीप, जो आर्कटिक महासागर के बर्फीले इलाके में स्थित है। दुनिया के इस अनोख द्वीप पर मरना और जन्म लेना दोनों ही गैरकानूनी है। बर्फ से ढके पहाड़, चमचमाते ग्लेशियर और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नजारे इसे किसी जन्नत जैसा खूबसूरत बनाते हैं, पर इस स्वर्ग जैसी जगह के कुछ ऐसे कानून हैं, जो इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग बना देते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई देशों के नागरिक बिना वीजा के स्वालबार्ड जा सकते हैं। हालांकि, यहां पहुंचने के बाद स्थानीय नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए स्वालबार्ड सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे कानूनों और रहस्यमयी जीवनशैली के कारण भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है। स्वालबार्ड में

किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसे वहीं दफनाने की अनुमति नहीं है। इसकी वजह बेहद दिलचस्प है। दरअसल यहां सालभर इतनी कड़ाके की ठंड रहती है कि जमीन हमेशा जमी रहती है। ऐसे में शव दफन भी हो जाएं तो वर्षों तक प्राकृतिक रूप से गल नहीं पाते। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे पुराने वायरस और बैक्टीरिया भी सुरक्षित रह सकते हैं, जो भविष्य में खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या उसकी हालत नाजुक होती है, तो उसे पहले ही नॉर्वे की मुख्य भूमि पर भेज दिया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वहीं इलाज और अंतिम संस्कार किया जा सके। सिर्फ मौत ही नहीं, स्वालबार्ड में बच्चे का जन्म देना भी संभव नहीं है। यहां कोई आधुनिक मैटर्निटी या डिलीवरी अस्पताल नहीं है।

यही वजह है कि जैसे ही किसी महिला की डिलीवरी का समय नजदीक आता है, उसे मेनलैंड पर भेज दिया जाता है, जहां सुरक्षित तरीके से बच्चे का जन्म कराया जाता है। इस द्वीप की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यहां इंसानों से ज्यादा पोलर बियर रहते हैं। ऐसे में यहां रहने वाले लोग अक्सर बाहर निकलते समय सुरक्षा के लिए हथियार खासकर बंदूकें साथ रखते हैं। कई इलाकों में बिना सुरक्षा के जाना खतरनाक माना जाता है।

नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री को 4 साल की जेल, पूर्व गृह मंत्री भी नपे

काठमांडू। नेपाल के बहुचर्चित फर्जी भूटानी शरणार्थी घोटाले में काठमांडू की एक स्थानीय अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए देश के दो शीर्ष राजनेताओं को जेल की सजा सुनाई है। नेपाली नागरिकों को फर्जी तरीके से भूटानी शरणार्थी बताकर अमेरिका भेजने के इस सनसनीखेज रैकेट में पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी को चार साल और पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खांड को दो साल जेल की सजा सुनाई गई है। काठमांडू जिला अदालत के न्यायाधीश तेज बहादुर खड़का की पीठ ने इस मामले में दोषी ठहराए गए कुल 16 लोगों की सजा का ऐलान किया है। सजा के साथ-साथ रायमाझी पर 40,000 नेपाली रुपये और खांड पर 20,000 नेपाली रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है।

रेप की कोशिश की परिभाषा पर बवाल, महिला आयोग और सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

पटना। देशभर में पटना और इलाहाबाद हाईकोर्ट की रेप की कोशिश से जुड़ी कुछ टिप्पणियों पर गहरा विवाद छिड़ गया है। इन अदालतों ने अलग-अलग मामलों में कहा था कि महज महिला का सलवार उतारना या स्तन दबाना रेप की कोशिश नहीं। इन विवादित बयानों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी इस पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने स्पष्ट किया कि यौन अपराधों की परिभाषा तय करते समय केवल शारीरिक शोषण को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बल दिया कि पीड़िता की गरिमा, उसकी सहमति, घटना से उसके मन में पैदा हुआ भय और मानसिक पीड़ा को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। महिला आयोग की अध्यक्ष रहाटकर ने चेतावनी दी कि यदि न्यायिक प्रक्रिया कानून की तकनीकी परिभाषाओं तक सीमित रह जाएगी और पीड़िता के वास्तविक अनुभवों व कानून

की मूल भावना को नजरअंदाज करेगी, तो न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा, उनके शारीरिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन हाईकोर्ट के फैसलों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और देश की सभी अदालतों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता पर बनी नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी कमेटी की रिपोर्ट को तुरंत सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट्स की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाए। साथ ही, राज्यों को सभी पुलिस स्टेशनों को इन नियमों का पालन करने के निर्देश जारी करने को कहा गया है ताकि एफआईआर दर्ज करते समय और चार्जशीट दाखिल करते समय इन संवेदनशील पहलुओं का ध्यान रखा जा सके।

यह पूरा विवाद न्याय व्यवस्था में पीड़िता-केंद्रित दृष्टिकोण और कानून की मूल भावना को बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर करता है, ताकि महिलाओं को पूरा न्याय मिल सके और उनका विश्वास कायम रहे।

पुश्तैनी सोना बेचने पर भी बिल जरूरी: टैक्स के नियमों को समझें

मुंबई। जब भी आप घर में रखी सोने की ज्वैलरी, सिक्के या बिस्किट बेचने की सोचते हैं, तब सिर्फ उसकी मौजूदा कीमत ही मायने नहीं रखती। दरअसल, इस पर लगने वाला टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि वह सोना आपने खुद खरीदा था, किसी से तोहफे में मिला था या विरासत में मिला है। इन तीनों ही स्थितियों में टैक्स के नियम अलग-अलग होते हैं, जिन्हें बेचना शुरू करने से पहले समझना बेहद जरूरी है, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। यदि आपने अपनी ज्वैलरी खुद खरीदी है और 24 महीने बाद बेचते हैं, तब मुनाफे पर 12.5 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स लगेगा। वहीं, अगर 24 महीने पूरे होने से पहले बेच दिया जाता है, तब मुनाफा आपकी कुल आय में जुड़ जाएगा और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देना होगा।

लेकिन विरासत में मिले सोने पर तुरंत कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब आप बेचते हैं, तब टैक्स देना पड़ता है। यहां खास बात यह है कि टैक्स की गणना करते समय सोने के पहले मालिक, यानी आपके माता-पिता या दादा-दादी ने गहने को कब

और कितने में खरीदा था, उसी को आधार माना जाएगा। उनका होल्डिंग पीरियड भी आपके साथ जुड़ जाता है, जिससे अक्सर यह सीधे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है।

तोहफे में मिले सोने के नियम भी भिन्न हैं। यदि यह सोना माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन या अन्य निर्धारित रिश्तेदारों से मिला है, तब प्राप्त करने पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, अगर किसी गैर-रिश्तेदार से एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक का सोना तोहफे में मिलता है, तब उसकी पूरी कीमत अन्य स्रोतों से आय के तहत टैक्सेबल हो सकती है। इस सोने को बेचने पर भी टैक्स का आकलन पिछले मालिक की खरीद कीमत और होल्डिंग पीरियड के आधार पर ही होगा।

टैक्स बचाने और सही गणना के लिए सोने की खरीदारी के सभी बिल संभालकर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्वैलरी खरीदते समय चुकाया गया 3 प्रतिशत जीएसटी, मेकिंग चार्ज और उस पर दिया गया जीएसटी भी खरीद लागत में शामिल किया जा सकता है। इससे आपकी कैपिटल गेन की राशि कम होगी और टैक्स का बोझ भी घट सकता है। इसी तरह, सोना बेचते समय दिए गए ब्रोकरेज या अन्य ट्रांसफर खर्च भी कुछ मामलों में घटाए जा सकते हैं।

डिजिटल गोल्ड पर भी भौतिक सोने जैसे ही टैक्स नियम लागू होते हैं। हालांकि, गोल्ड ईटीएफ (ईटीएफ) के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पीरियड सिर्फ 12 महीने है, जिससे यह टैक्स के लिहाज से अधिक फायदेमंद हो सकता है। सोने की बिक्री से जुड़े टैक्स को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए यह समझना आवश्यक है कि सोना आपने खरीदा था, उपहार में मिला था या विरासत में प्राप्त हुआ है।

ताजा खबर

संक्षिप्त

38 सिविल जजों को पदोन्नति, जूनियर से बने सीनियर डिवीजन जज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में पदस्थ 38 सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर पदोन्नत किया है। सभी को मार्च और अप्रैल की विभिन्न तिथियों से पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सिविल जज जूनियर अंजली पांडेय, अंकिता अग्रवाल, दिव्या गोयल, ऐश्वर्या दीवान, शैलेश कुमार वशिष्ठ, आफरीन बानो, हर्षि अग्रवाल, मीनू नंद, प्रज्ञा अग्रवाल, स्वर्णा देहरे, काम्या अय्यर, सारिका नंदे, अजय सिंह मीणा, रश्मि मिश्रा, शाश्वत दुबे, कोनिका यादव, आशीष कुमार चांदहे, गुरु प्रसाद देवांगन, कुमुदिनी गर्ग, अंकिता यदु, उन्नति महेश्वर, सिद्धार्थ आनंद सोनी, तनया ब्राह्मी, नीति, मनीष कुमार, साक्षी ध्रुव, पार्थ दुबे, जेनिफर लकड़ा, धारिणी राणा, प्रांजलि नेताम, राजेश खलको, अजय लकड़ा, ध्रुवराज ग्वाल, शिवेंद्र कुमार टेकाम, श्वेता ठाकुर, पुनीत तिग्गा, डिंपल और प्रवीण कुजूर को सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर पदोन्नत किया गया है।

बुकिंग रद्द होने पर भी अब होगा जीएसटी रिफंड, सेंट्रल जीएसटी ने राज्यों को भेजी चिट्ठी

रायपुर। सेंट्रल जीएसटी की ओर से सभी राज्यों को चिट्ठी भी भेजी गई है। इसमें मकान, बंगले, फ्लैट खरीदने या किसी कार्यक्रम के लिए बुकिंग कराने के बाद उसे रद्द कराने पर काटी गई जीएसटी को वापस करने का निर्देश दिया गया है। राजधानी समेत राज्यभर में ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में हैं, जिन्हें प्लॉट, दुकान, व्यावसायिक परिसर या किसी अन्य सेवा को रद्द कराने के बाद जीएसटी की वापसी नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार के सख्त निर्देशों के बाद राज्य आयुक्त ने भी नए सर्कुलर के अनुसार रिफंड दावों का निपटारा करने को कहा है। इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिन्होंने किसी सेवा के लिए एडवांस रकम या जीएसटी का भुगतान किया था, लेकिन बाद में बुकिंग रद्द कर दी गई। अभी तक कई मामलों में काम करने वाले लोग जीएसटी का क्रेडिट नोट जारी नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में लोग न तो सप्लायर से पैसे ले पा रहे थे, और न ही सरकार से भी रिफंड लेने का कोई स्पष्ट निर्देश था। सीजीएसटी अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों को राहत देने के लिए ही नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को हो ही होगा। इससे बुकिंग के नियम भी आसान होंगे।

छत्तीसगढ़ में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रथम, 81 प्रतिशत से अधिक बुजुर्गों के बने कार्ड

रायपुर. आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रूपए तक का निःशुल्क और कैशलेस इलाज मिलता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संचालित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत वय वंदन योजना के सफल क्रियान्वयन में यह जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर उभरा है। 15 जुलाई को जारी राज्य स्तरीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह सफलता जिला प्रशासन की दूरदर्शिता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समर्पण को रेखांकित करती है।

रथयात्रा हमारी आस्था, लोकसंस्कृति, सामाजिक समरसता और जनभागीदारी का जीवंत महापर्व : मुख्यमंत्री साय

राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथयात्रा में हुए शामिल

रायपुर. राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान श्रीजगन्नाथ मंदिर में आयोजित भव्य रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए। दोनों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीजगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पारंपरिक श्छेरा-पहराश् की रस्म निभाते हुए प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। वैदिक मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और जयघोष के बीच भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशेष विधि-विधान के साथ मंदिर से रथ तक लाया गया। इसके पूर्व राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पारंपरिक रीति से सोने की झाड़ू द्वारा छेरा-पहरा की रस्म निभाकर रथमार्ग का प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात महाप्रभु की प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक रथ पर विराजित किया गया और रथयात्रा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को रथयात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा सनातन

संस्कृति, सामाजिक समरसता, लोकपरंपरा और जन-जन की आस्था का महापर्व है। यह उत्सव समाज को सेवा, समर्पण, समानता और लोककल्याण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ किसानों के आराध्य और अन्नदाता के रक्षक माने जाते हैं। उनकी कृपा से समय पर वर्षा होती है, खेतों में हरियाली आती है, धान की बालियों में दूध भरता है और किसानों के घरों में समृद्धि का आगमन होता है। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना की कि इस वर्ष प्रदेश में भरपूर वर्षा हो, कृषि समृद्ध हो, किसानों की मेहनत सफल हो और छत्तीसगढ़ निरंतर विकास एवं खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का दिव्य आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों पर बना रहे तथा सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का संचार हो। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज में सद्भाव, एकता और सामूहिक चेतना को भी नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष पुरी की विश्वविख्यात रथयात्रा की तर्ज पर यह आयोजन अत्यंत श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होता है। छेरा-पहरा की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भगवान के समक्ष सभी समान हैं और सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। उल्लेखनीय है कि ओडिशा का पड़ोसी राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ में भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति विशेष श्रद्धा और आस्था रही है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में रथयात्रा का आयोजन उत्साहपूर्वक किया जाता है। उत्कल संस्कृति और दक्षिण कोसल की सांस्कृतिक परंपराओं के बीच यह पर्व एक सशक्त सेतु का कार्य करता है। इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विभिन्न निगम-मंडलों एवं आयोगों के अध्यक्षगण, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। गुरूवार को राजधानी की सडक़ों में एक अलग ही माहोल बन गया। जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करने निकले। इस बीच भक्तों का जनशौलाब उमड़ पड़ा।

छोटे कारोबारों को मिलेगी आसान मंजूरी, सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑटो अप्रूवल जैसी सुविधाएं

छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग और कारोबार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज %छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026% पारित कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित (रिस्क बेस्ड) एवं विश्वास आधारित (ट्रस्ट बेस्ड) बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा। इस विधेयक का उद्देश्य उद्योगों एवं कारोबार की स्थापना और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालनों को कम करना तथा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अधिक पारदर्शी, तेज और उद्यम-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है। विधेयक के तहत उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण उनके आकार और गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न जोखिम श्रेणियों में किया जाएगा। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारों को सरल एवं त्वरित मंजूरी मिलेगी, जबकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध स्वीकृति की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। इससे छोटे कारोबारियों को बड़े उद्योगों जैसी जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत कम जोखिम वाले उद्यमों में बार-बार होने वाले विभागीय निरीक्षणों

के स्थान पर सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा लाइसेंसधारी अभियंता, आर्किटेक्ट या अन्य अधिकृत पेशेवरों द्वारा प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे अनुमतियों की प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक जवाबदेह बनेगी। विधेयक के तहत हर वर्ष लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू की जाएगी। इससे उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार के विस्तार एवं संचालन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

एमएसएमई इकाइयों के लिए जल प्रदाय संबंधी अनुमति स्व-घोषणा के आधार पर, सोसायटी अथवा फर्म का पंजीयन समयबद्ध प्रक्रिया से तथा भवन अनुज्ञा सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की जा सकेगी। निर्धारित समय-सीमा में संबंधित विभाग द्वारा निर्णय नहीं लेने की स्थिति में पात्र मामलों में अनुमति स्वत: स्वीकृत (ऑटो अप्रूवल) मानी जाएगी। हालांकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में तकनीकी परीक्षण एवं भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

विधेयक के अंतर्गत राज्य शासन के 8 विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली 43 सेवाओं को जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली के दायरे में शामिल किया गया है। आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका परिषद की मंजूरी से अतिरिक्त सेवाएं भी इसमें जोड़ी जा सकेंगी।

विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति इसके क्रियान्वयन और अनुश्रवण की जिम्मेदारी निभाएगी। दोनों समितियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी।

इस सुधार से राज्य के 15 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि भरोसे, स्व-घोषणा और समयबद्ध सेवाओं पर आधारित यह व्यवस्था कारोबार शुरू करने और संचालित करने में लगने वाले समय एवं लागत को कम करेगी, जबकि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और परीक्षण की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।

%छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026% राज्य में पारदर्शी, सरल, पूर्वानुमेय और निवेश-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियां शुरू

राज्य शासन ने जारी किए स्वतंत्रता दिवस आयोजन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने स्वतंत्रता दिवस 2026 को पूरे प्रदेश में गरिमामय, भव्य और प्रेरणादायी ढंग से मनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस विशेष होने जा रहा है, क्योंकि इस मौके पर राष्ट्रगीत श्वंदे मातरम्श के 150 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव भी मनाया जाएगा। शासन द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों और विभागीय प्रमुखों को आयोजनों की समुचित निगरानी के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

राजधानी रायपुर के स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य राज्य स्तरीय समारोह 15 अगस्त की प्रातः 9:00 बजे आयोजित किया जाएगा। इस भव्य समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। ऐतिहासिक अवसर वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सभी शासकीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन अनिवार्य किया गया है। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (पुरुष व महिला), नगर सेना, एनसीसी तथा बैंड प्लाटून की टुकड़ियाँ भाग लेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे। जिला मुख्यालयों में शासन द्वारा नामित मंत्रीगण ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। यहाँ स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जनपद पंचायत मुख्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिकाओं व पंचायतों में उनके अध्यक्ष व सरपंच तथा बड़े गांवों में ग्राम प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे। इन स्थलों पर राष्ट्रीय गान, भाषण तथा देश की एकता एवं अखण्डता का संदेश प्रसारित किया जाएगा। जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तरीय समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को विशेष व सम्मानपूर्वक रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी होने वाले सरकारी विज्ञापन स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और छत्तीसगढ़ के शहीदों को समर्पित होंगे। इन विज्ञापनों का प्रकाशन 15 अगस्त के दिन समाचार पत्रों में सुनिश्चित किया जाएगा।

रेलवे के आधुनिकीकरण से यात्री सुविधाओं, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रायपुर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री दयानन्द ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन समारोह के लिए केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को आमंत्रण पत्र भेंट किया। भेंट के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों पर विकसित आधुनिक यात्री सुविधाओं, अधोसंरचना उन्नयन तथा स्टेशनों के नए स्वरूप को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है, जिसका लाभ सीधे आम नागरिकों और प्रदेश के समग्र विकास को मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय रेल

मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे आज अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यात्री सेवाओं और विश्वस्तरीय अधोसंरचना से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, व्यापार, पर्यटन और जनसुविधाओं की जीवनरेखा है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आधुनिक रेल अधोसंरचना का विस्तार तेज़ी से हो रहा है। रेल संपर्क के सुदृढ़ होने से प्रदेश में निवेश, उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा आम नागरिकों का आवागमन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से देशभर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित एवं नवीनीकृत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुगम, सुरक्षित एवं यात्री-अनुकूल बनाकर देश की परिवहन व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

प्रोजेक्ट धड़कन के तहत 6,224 बच्चों की जांच

तीन बच्चों का सत्य साई हॉस्पिटल रायपुर में निःशुल्क हृदय ऑपरेशन सफल

रायपुर. दूरस्थ एवं आदिवासी बहुल जिला नारायणपुर में बच्चों को जन्मजात हृदय रोग से समय पर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट धड़कन की शुरुआत की गई।

ताकि गंभीर हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उनका निःशुल्क उपचार कराया जा सके। योजना के अंतर्गत आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) टीम द्वारा जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में व्यापक स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया गया। अब तक कुल 6,224 बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है।

जांच के दौरान हृदय संबंधी गंभीर समस्या से ग्रसित 03 बच्चों की पहचान की गई। इनमें पारुल

दुग्गा (1.5 वर्ष), नायशा (3 वर्ष) एवं अनुष्का मंडावी (5 वर्ष) शामिल हैं। आरबीएसके टीम द्वारा आवश्यक जांच एवं परामर्श के बाद इन बच्चों को सत्य साईं हॉस्पिटल, रायपुर रेफर किया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा तीनों बच्चों का सफल एवं निःशुल्क हृदय ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद तीनों बच्चों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार है और वे स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हैं। यह उपलब्धि प्रोजेक्ट धड़कन एवं आरबीएसके टीम की सक्रिय कार्यप्रणाली, समय पर स्क्रीनिंग तथा त्वरित रेफरल व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है।

जिला स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच निरंतर जारी है। योजना का उद्देश्य जन्मजात हृदय रोग से पीडित बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि वे स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन जी सकें।

जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। यदि बच्चे में सांस फूलना, जल्दी थक जाना, वजन कम बढ़ना अथवा बार-बार बीमार पड़ने जैसे लक्षण दिखाई दें, तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जांच अवश्य कराएं।

पीएम मातृ वंदना योजना में 14.49 लाख से अधिक माताओं को 558.93 रूपये करोड़ की डीबीटी सहायता

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील

रायपुर. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाने में सफल रहा है। पारदर्शी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली, राज्य सरकार की सतत निगरानी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पित प्रयासों से प्रदेश की लाखों गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने योजना की इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ मातृ सुरक्षा, पोषण और महिला कल्याण के क्षेत्र में लगातार

नए मानक स्थापित कर रहा है।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश में अब तक 14 लाख 49 हजार 309 पात्र हितग्राहियों का सफल पंजीयन किया जा चुका है। इन सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 558.93 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भुगतान व्यवस्था के कारण लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिये के समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी आधारित मातृत्व सहायता योजनाओं में से एक है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की केस स्टडी के अनुसार यह योजना गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। योजना के सकारात्मक प्रभाव से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने में भी सहायता मिली है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व, बेहतर पोषण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है तथा पात्र हितग्राहियों का समयबद्ध पंजीयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा, ष्यदि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी या किसी प्रकार की राशि की मांग की जाती है, तो उसकी बातों में बिल्कुल न आएं। ऐसे कॉल साइबर ठगों के हो सकते हैं। किसी भी संदिग्ध स्थिति में तत्काल अपनी निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा संबंधित विभाग से संपर्क करें। साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता और सतर्कता ही है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हितग्राही महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही योजना से जुड़ी सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी महिला ठगी का शिकार न बने।

योजना के नाम पर साइबर ठगी से रहें सतर्क

योजना की सफलता के बीच मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने साइबर अपराधियों की सक्रियता को लेकर प्रदेशवासियों को विशेष रूप से सचेत किया। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर फर्जी फोन कॉल कर महिलाओं से ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी अथवा राशि की मांग किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

6 साल के मासूम के गले में फंसा सिक्का, डॉक्टरों ने बचाई जान

रायपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर के कान, नाक एवं गला (ईएनटी) विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए एक 6 वर्षीय मासूम की जान बचा ली है। बैगा जनजाति के इस बालक ने खेलते समय गलती से सिक्का निगल लिया था, जो उसकी आहार नली (अन्ननली) में फंस गया था। डॉक्टरों की टीम ने बेहद जटिल और आपातकालीन स्थिति में सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सिक्के को बाहर निकाला जानकारी के अनुसार, बिलासपुर जिले के कोटा तहसील अंतर्गत ग्राम सरगोंड का निवासी 6 वर्षीय बालक नरेंद्र खेलते समय सुबह करीब 7 बजे अचानक सिक्का निगल गया। इसके तुरंत बाद उसे कुछ भी निगलने में अत्यधिक परेशानी होने लगी। परिजन आनन-फानन में उसे पेंड्रा के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। बालक को शाम करीब 6.30 बजे सिम्स लाया गया, जिसके बाद अस्पताल का पूरा अमला सक्रिय हो गया। रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह ने तत्काल एक्स-रे कर अन्ननली के ऊपरी भाग (श्वासनली के मुहाने के ठीक पीछे) में फंसे सिक्के की सटीक लोकेशन की पहचान की।

मेसी ने बनाया महारिकार्ड

अटलांटा। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने अपने जादुई प्रदर्शन से टीम को फीफा विश्वकप फाइनल में पहुंचाने के दौरान ही एक नया विश्व रिकार्ड भी अपने नाम किया है। इंग्लैंड के खिलाफ हुए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में मेसी ने दो गोल करने में असिस्ट (सहायता) की इससे उनकी टीम को 2-1 से जीत मिली। इसके साथ ही मेसी के नाम अब विश्वकप में कुल 12 असिस्ट दर्ज हो गए हैं। इन 12 में से 10 असिस्ट उन्होंने टूर्नामेंट के बेहद दबाव भरे नॉकआउट मुकाबलों में किए हैं, जो उनकी असाधारण खेल समझ और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता को दिखाते हैं। आंकड़ों के अनुसार मेसी इस अभूतपूर्व मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। गौरतलब है कि विश्व कप के पूरे इतिहास में किसी अन्य खिलाड़ी ने 8 से अधिक असिस्ट नहीं किए हैं, जो मेसी की उपलब्धि को और भी खास बना देता है।

मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने गोल के कई प्रयास किए लेकिन कोई भी टीम सफलता हासिल नहीं कर पाई। वहीं दूसरे हाफ की शुरूआत में इंग्लैंड ने 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन के गोल से1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद अर्जेंटीना की ओर से लगातार प्रयास जारी रहे, और मुकाबले के आखिरी 7 मिनटों में टीम ने एक जबरदस्त वापसी करते हुए मैच का रुख ही पलट दिया। मैच के 85वें मिनट में मेसी के एक बेहतरीन पास पर एंजो फर्नांडेज ने एक गोल दाग दिया। जिससे स्कोर 1-1 से बराबरी पर आ गया। इसके बाद मेसी ने फिर असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार पास दिया, जिसे लाउतारो मार्टिनेज ने हेडर की मदद से गोल में बदलने में कोई गलती नहीं करते हुए अर्जेंटीना को मैच में 2-1 से आगे कर दिया।

जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने कसा टीम इंडिया पर तंज, कहा - 'जो रूट एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं'

नई दिल्ली। भारत को इंग्लैंड के हाथों दूसरे वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है. दरअसल, भारत और इंग्लैंड के बीच बीते गुरुवार को दूसरा वनडे मैच खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में 10 विकेट खोकर 233 रन बनाए. इंग्लैंड की टीम ने इस लक्ष्य को 44.1 ओवर में 6 विकेट पर 135 रन बनाकर हासिल कर लिया. इसके साथ ही इंग्लैंड ने 35 बॉल बाकी रहते हुए 4 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया.

इस जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने बयान बयान दिया है. उन्होंने अपने इस बयान पर टीम इंडिया पर इनडायरेक्टली तंज कसा है, इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी खिलाड़ी जो रूट के बारे में बड़ी बात बोली है. उन्होंने क्या कहा है, आइए इस बारे में जानते हैं.

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि, 'हम अभी भी सीरीज में हैं, इसलिए रविवार का इंतजार कर रहे हैं. मुझे लगा कि यह एक बेहतरीन प्रयास था. 30 ओवर के बाद उनका स्कोर 3 विकेट पर 180 रन था और लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर बनेगा. ऐसे कुछ अच्छे समय थे जब सैम और जैक एक साथ गेंदबाजी कर रहे थे. मुझे लगा कि उन्होंने

दोनों छोरों को वास्तव में अच्छी तरह से पकड़ रखा है और फिर अंत में उन्हें 60 रन पर 7 विकेट आउट करना हैरान करने वाला था. उन्होंने आगे कहा कि, 'हम इसी आधार पर एकादश का चयन करने का प्रयास कर रहे थे और किसी और दिन हमें एक और स्पिनर लाना पड़ सकता है. लेकिन आज हमने सोचा कि अतिरिक्त सीमर सही विकल्प है. जो रूट एक अभूतपूर्व खिलाड़ी हैं. आप चेंजिंग रूम में भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. वह एक महान व्यक्ति है और वह हमेशा तब उपस्थित होता है जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है. मुझे कुछ साल पहले खेली गई उनकी एक पारी याद है, जहां मुझे लगता है कि उन्होंने केवल तीन चौके लगाए थे और उन्होंने 100 रन बनाए थे, जो धमाकेदार थे'. हैरी ब्रुक ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर बात करते हुए कहा कि, 'वास्तव में हम हर दिन को वैसे ही लेते हैं जैसे वह आता है. अगर हमें क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करना ही होगा. लेकिन हम अब रविवार की ओर देख रहे हैं और देखेंगे कि वहां क्या परिस्थितियां हैं और उन्हें हराने की कोशिश करेंगे'.

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला लोकलटाइमजोन के हिसाब से दोपहर 1 बजे शुरू होगा. वहीं, भारत में ये मैच शाम 3.30 बजे शुरू होगा. ऐसे में टॉस के लिए दोनों कप्तान 3 बजे मैदान पर उतरे हैं.

रोहित-विराट ने साझेदारी में पूरे किए 8000 रन

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी. सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे. कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. इसके बाद रोहित और विराट के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई. इस साझेदारी के साथ रोहित और विराट ने मिलकर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. दरअसल रोहित और विराट की जोड़ी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सभी फॉर्मेट में सबसे बड़ी साझेदारियां करने वाली तीसरी जोड़ी बन गई है.

भारतीय टीम के दो मौजूदा दिग्गज

बल्लेबाजों, रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने एक बड़ा कीर्तिमान बनाया है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में रोहित और विराट के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई. इसी के साथ रोहित-विराट की जोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली तीसरी जोड़ी बन गई है. ये दोनों दिग्गज भारत के लिए अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 8008 रनों की शानदार साझेदारी कर चुके हैं.

भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की महान जोड़ी के नाम दर्ज है. इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर अपने करियर के दौरान कुल 12400 रनों की ऐतिहासिक साझेदारियां की हैं. वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी है. इन दोनों दिग्गजों ने अपने करियर में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,037 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई. सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने मिलकर टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में संभालते हुए कुल 7,626 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कीं थीं. इसके अलावा, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी आती है, जिन्होंने कुल 7199 रनों की साझेदारी की है.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद घरेलू काउंटी टीम डरहम के लिए मैदान में वापसी करेंगे बेन स्टोक्स

लंदन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बेन स्टोक्स अपनी घरेलू काउंटी टीम डरहम के लिए मैदान में वापसी करेंगे। स्टोक्स 21 जुलाई से शुरू होने वाले घरेलू वनडे कप में डबीर्शायर के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। वह डरहम के लिए खेलेंगे और फिटनेस ठीक रहने पर 50 ओवर के मेट्रो बैंक कप और काउंटी चैंपियनशिप सीजन के बाकी सभी मैचों के लिए वह उपलब्ध रहेंगे।

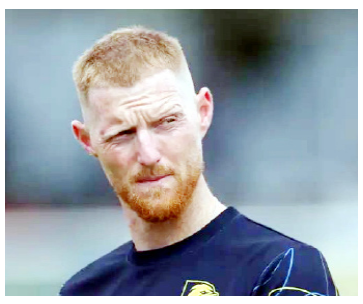

उनकी शुरूआत अगले सप्ताह डबीर्शायर के खिलाफ होने वाले मैच से हो सकती है। डरहम के मुख्य कोच रयान कैंपबेल ने कहा, वह अब एक संन्यास ले चुके टेस्ट सुपरस्टार हैं, लेकिन उन्होंने डरहम के क्रिकेटर के रूप में ड्यूटी ज्वाइन कर ली है।

गुरनूर बराड़ को बल्लेबाज पर गेंद फेंकना पड़ा भारी, मिला एक डिमेरिट अंक

बर्मिंघम। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ विवादों में घिर गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के लिए गुरनूर को आधिकारिक चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही उनके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है।

24 महीने की अवधि में गुरनूर बराड़ का यह पहला अपराध है। इसके कारण आईसीसी ने सिर्फ एक ही अंक जोड़े हैं। यह घटना इंग्लैंड की पारी के आठवें ओवर के दौरान हुई, जब फील्डिंग कर रहे गुरनूर ने गेंद को फील्ड करने के बाद अनुचित और खतरनाक तरीके से सीधे इंग्लिश बल्लेबाज की तरफ थ्रो कर दिया। मैदान पर मौजूद अंपायरों ने इसे आईसीसी आचार संहिता के नियम 2.9 का उल्लंघन माना।

जापान में गूंजेगी भारत की हुंकार, इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में दमखम दिखाएंगे 17 जांबाज

चौपाल/नेरवा

जापान के हिमेजी (ओसाका) में 15 से 25 जुलाई तक होने वाली 101वीं शिगोकान एनिवर्सरी व ऑल जापान इंटरनेशनल फ्रेंडशिप कराटे प्रतियोगिता में भारत का दमखम देखने को मिलेगा। इस वैश्विक महाकुंभ में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिगोकान गोजूरियू कराटे इंडिया की 17 सदस्यीय टीम पूरी तरह कमर कस चुकी है, जिसमें पांच लड़कियां और 12 लडके शामिल हैं। टीम मैनेजर सैनसाई पीएस पंवार ने बताया कि भारतीय चुनौती का नेतृत्व मुख्य कोच सैनसाई अनिल कुमार जिस्टा और सहायक कोच सैनसाई रेखा सिंह पंवार कर रहे है। इस दल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें रूट्स कंट्री स्कूल बागी के सर्वाधिक 10 होनहार एथलीटों ने जगह बनाई है। टूर्नामेंट के लिए रवाना होने से पहले गुरुवार को पूरे भारतीय दल ने संस्था के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर और तकनीकी निदेशक सैनसाई जय प्रकाश से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन किया।

भारत की ओर से पदक जीतने के पक्के इरादे के साथ आधिकारिक स्टाफ के साथ रियांश, अबीर, ध्रुव, अंश, मन्नत, अरध्यानश, ईशमीत, जैसमीन, अक्शित, आक्षी, ऊनीत, चमन, शार्वी और दिग्विजय सिंह जैसे कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी कला का हैरतअंगेज प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

कारोबार

एक साल से भी कम समय में ग्रो ने मारी बाजी, दर्ज किया शानदार मुनाफा

लंबे समय से शीर्ष पर काबिज एंजेल वन को पछाड़कर नंबर वन का ताज हासिल किया

नई दिल्ली। भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो ने लंबे समय से शीर्ष पर काबिज एंजेल वन को पछाड़कर नंबर वन का ताज हासिल कर लिया है।

यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही के आंकड़ों के साथ 15 जुलाई को सामने आया है, जहां ग्रो ने नोशनल एवरेज डेली टर्नओवर (एनएडीटी) के मामले में एंजेल वन को मात दी है। जारी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रो का नोशनल एवरेज डेली टर्नओवर 2.43 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि एंजेल वन का टर्नओवर 2.37 लाख करोड़ रुपये रहा। नोशनल टर्नओवर किसी प्लेटफॉर्म पर एक दिन में हुए कुल सौदों की औसत वैल्यू को दशार्ता है, जो बाजार में कंपनी की गतिविधि और प्रभाव को दशार्ता है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रो ने कमोडिटी कारोबार में बहुत पहले एंट्री नहीं की थी। कंपनी ने जुलाई 2025 में चुनिंदा

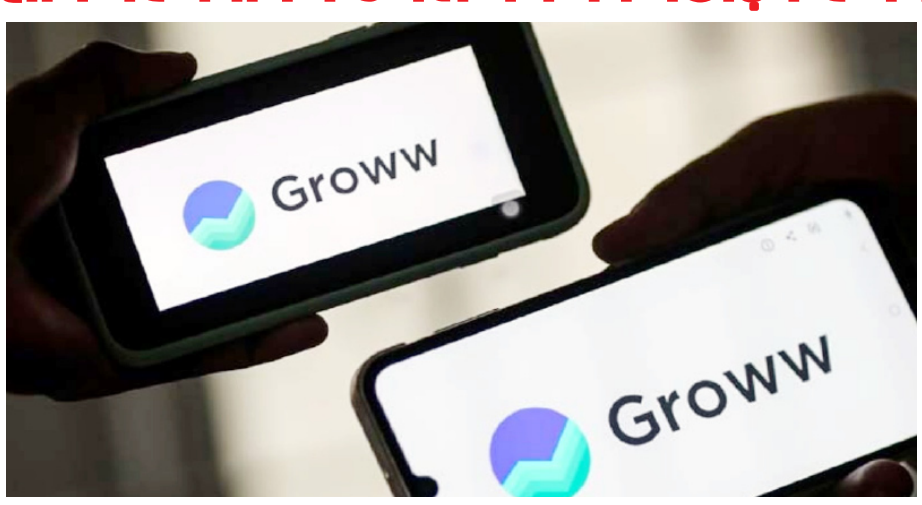

ग्राहकों के लिए यह सेवा शुरू की थी और सितंबर तक इसे सभी यूजर्स के लिए खोल दिया। यानी एक साल से भी कम समय में ग्रो ने उस बाजार में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया, जहां एंजेल वन लंबे समय से सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। इस तेजी के पीछे ग्राहकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी के कमोडिटी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 27 हजार ग्राहक थे, जो जून 2026 के अंत तक बढ़कर 4.35 लाख हो गई। आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में ग्रो की कमोडिटी मार्केट में हिस्सेदारी 28.6 फीसदी रही, वहीं एंजेल वन की हिस्सेदारी करीब 26.5 फीसदी रही। इस मामले में जेरोधा लगभग 12 फीसदी हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है। कमोडिटी कारोबार का असर अब ग्रो की कमाई पर भी साफ दिख रहा है। अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में कंपनी की कुल आय का 4.9 फीसदी हिस्सा कमोडिटी बिजनेस से आया। ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेंस गैराज वेंचर्स ने जून 2026 तिमाही में 735 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले 94 फीसदी ज्यादा है। इसी दौरान कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू भी 66 फीसदी बढ़कर 1,501 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का कहना है कि वह अपनी आय को सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर निर्भर नहीं रखेगी और अलग-अलग कारोबार से आय बढ़ाएगी। कमोडिटी, मार्जिन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और लोन जैसी सेवाओं के विस्तार से ग्रो अब सिर्फ शेयर ट्रेडिंग ऐप नहीं, बल्कि एक व्यापक वित्तीय सेवा मंच बनता जा रहा है।

शेयर बाजार में उछाल : सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा तो निफ्टी 24150 के पार, रुपया भी मजबूत

नई दिल्ली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स 400 से अधिक अंक चढ़ा, निफ्टी 24,150 के पार पहुंचा। इंफोसिस में 3 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि वैश्विक बाजार गिरे। रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में शुरूआती कारोबार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 400 से अधिक अंक चढ़कर 77,616.73 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 24,150 के स्तर को पार कर 24,188.35 पर बंद हुआ। इस दौरान इंफोसिस के शेयरों में 3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं विप्रो के शेयर 1 फीसदी गिर गए।

बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि निफ्टी मौजूदा समर्थन स्तरों से ऊपर बना रहेगा। यह 24,250 से 24,350 के क्षेत्र की ओर वापसी

कर सकता है। यह क्षेत्र निफ्टी की हालिया समेकन सीमा का ऊपरी छोर है। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद भारतीय बाजार मजबूत रहे। सुबह 10:50 बजे टोक्यो के समय के अनुसार, एसएंडपी 500 वायदा 0.5 फीसदी गिर गया। जापान का टॉपिक्स 2.4 फीसदी नीचे रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.8 फीसदी गिरा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.8 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 1 फीसदी नीचे आया। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में भी 0.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ। रुपया शुरूआती कारोबार में 96.28 के स्तर पर पहुंच गया।

भारतीय बाजार में यह उछाल क्यों आया?

भारतीय शेयर बाजार में यह उछाल वैश्विक गिरावट के विपरीत रहा। सेंसेक्स में 429.86 अंकों की वृद्धि हुई, जो 0.55 फीसदी का लाभ दशार्ता है। निफ्टी में भी 115.60 अंकों की बढ़त दर्ज की गई, जो 0.48 फीसदी की वृद्धि है। इंफोसिस जैसे प्रमुख शेयरों में वृद्धि ने बाजार को सहारा दिया। यह घरेलू निवेशकों के मजबूत विश्वास को दशार्ता है।

रुपये की मजबूती का क्या अर्थ है?

रुपये में 14 पैसे की वृद्धि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उसकी मजबूती को दशार्ती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। मजबूत रुपया आयात को सस्ता बनाता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर सकता है। रुपये का 96.28 पर पहुंचना बाजार में विश्वास को बढ़ाता है।

गेहूं एक महीने में 8 फीसदी महंगा, बढ़ सकती हैं खाद्य तेल की कीमतें

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन से पहले गेहूं और खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर रूस-यूक्रेन क्षेत्र में आपूर्ति संबंधी चुनौतियों और घरेलू बाजार में उत्पादन तथा स्टॉक को लेकर चिंताओं के कारण गेहूं के दाम ऊपर गए हैं। वहीं, सोयाबीन की बुआई, पाम तेल की सीमित उपलब्धता, बढ़ती आयात लागत और त्योहारी मांग के चलते खाद्य तेल भी महंगे बने रहने की संभावना है।

त्योहारी सीजन से ठीक पहले रसोई का बजट फिर बिगड़ सकता है। घरेलू बाजार में पिछले एक माह में गेहूं की कीमतें 8 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी आने की पूरी आशंका है।

काले सागर में आपूर्ति के बढ़ते जोखिमों के कारण शिकागो गेहूं वायदा पिछले सत्र में 5 फीसदी उछलने के बाद दो महीने के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है। यूक्रेन के बंदरगाह पर हुए हमलों से गेहूं निर्यात प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर, अजोव सागर और केर्च जलडमरूमध्य में प्रतिबंध से रूस का गेहूं निर्यात भी मुश्किल में आ गया है। इन व्यवधानों ने वैश्विक गेहूं बाजारों में एक जोखिम प्रीमियम जोड़ दिया है।

गेहूं की वैश्विक कीमतों में आए इस उछाल का असर भारतीय बाजार पर भी हुआ है। इस दौरान इंदौर मंडी में गेहूं के दाम सबसे अधिक 8.44 फीसदी तक बढ़े हैं। दिल्ली, कानपुर और कोटा जैसी प्रमुख मंडियों में कीमतें औसतन 3.5-4 फीसदी के बीच बढ़ी हैं। गेहूं उत्पादन का परिदृश्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि बढ़ता तापमान, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि पैदावार एवं अनाज की गुणवत्ता के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं। मौसम में हालिया व्यवधानों के कारण व्यापारियों ने अगले रबी सीजन के उत्पादन पूर्वानुमान को 11.35 करोड़ टन से घटाकर 11.40 करोड़ टन कर दिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन के बावजूद शुरूआती उम्मीदों से कम है।

खाद्य तेलों में तेजी के चार कारण

- इस साल सोयाबीन की खेती 6 फीसदी तक कम रहने की आशंका है। 15 दिनों में बारिश में सुधार नहीं हुआ, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी 5 से 7 फीसदी घट सकता है।
- वैश्विक बाजारों में पाम तेल की उपलब्धता में कमी और घरेलू बाजार में सरसों व सोयाबीन के पर्याप्त स्टॉक के चलते भारत ने आयात कम किया है, जिससे आने वाले समय में घरेलू स्टॉक पर दबाव बढ़ेगा।
- एफएमसीजी कंपनियों और स्टॉकिस्टों की मांग थोड़ी सुस्त जरूर है। लेकिन, अगस्त के पहले पखवाड़े से बाजार में रिकवरी आएगी और दिवाली तक त्योहारी मांग चरम पर होगी। यह मांग कीमतों को और ऊपर धकेलेगी।

महत्वपूर्ण ख़बर

जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

■ भोपाल। राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि "स्व. बाबूलाल गौर की प्रेरणा से गोविंदपुरा अंचल में जनसेवा और नव-निर्माण का जो महाअभियान प्रारंभ हुआ था, वह आज भी अनवरत गतिमान है। क्षेत्र का चहुंमुखी विकास और नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।" राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती गौर गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 57 में भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रही थी।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने क्षेत्रवासियों की सुख-सुविधाओं के लिए लगभग 81 लाख रुपये की लागत के विभिन्न लोक-कल्याणकारी निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। भगत सिंह चौराहे से शक्तिनगर तक सड़क के दोनों ओर 33 लाख रुपये की लागत से पेवर ब्लॉक का निर्माण ,शक्तिनगर सेक्टर-3 स्थित शिव मंदिर के समीप श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 लाख रुपये की लागत से शेड का निर्माण तथा स्थानीय युवाओं को खेल के आधुनिक संसाधन एवं रात्रिकालीन खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुभाष खेल मैदान में 40 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक फ्लड लाइट का भूमि - पूजन किया ।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा तकनीकी समिति में मध्यप्रदेश को मिला महत्वपूर्ण

■ भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश ने विद्युत क्षेत्र की साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) तथा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) द्वारा विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर-सीआईआई) के संरक्षण एवं सुरक्षा मूल्यांकन के लिए अनुरूपता मूल्यांकन ढांचा (कॉनफॉर्मिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क-सीएएफ) विकसित करने के लिये राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

मध्यप्रदेश बना निवेशकों की पहली पसंद

दिल्ली के दो बड़े आयोजनों में 20,193 करोड़ के मिले निवेश प्रस्ताव

भोपाल। मध्यप्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 तथा इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश" के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोनों आयोजनों में प्रदेश को 20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 27,592 लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों, उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश को देश का उभरता हुआ औद्योगिक एवं टेक्सटाइल हब बताया और उन्हें जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (ङ्मकर-2027) में भाग लेने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश निवेशकों को अनुकूल नीतियां, मजबूत अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और त्वरित प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों, साझेदारियों और एमओयू के माध्यम से मध्यप्रदेश देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में अपनी स्थिति और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

भारत टेक्स-2026 में टेक्सटाइल क्षेत्र को मिला बड़ा निवेश

भारत मंडपम में आयोजित टेक्सटाइल राउंडटेबल में प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, तकनीकी वस्त्र, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास और निवेश प्रोत्साहन पर विस्तृत चर्चा हुई। इस आयोजन में 1,592 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 15,700 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

दिल्ली निवेश संवाद में सात महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर

इंटरैक्टिव सेशन के दौरान एमपीआईडीसी ने निर्यात संवर्धन, ई-कॉमर्स, वैश्विक व्यापार, एमएसएमई और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सात महत्वपूर्ण समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। साथ ही रक्षा, डेटा सेंटर, आईटी, एआई, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण सहित अनेक क्षेत्रों

में निवेश अवसर प्रस्तुत किए गए। दिल्ली निवेश संवाद में रक्षा, डेटा सेंटर, ट्रांसफॉर्मर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इंजीनियरिंग और खिलौना उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 18,601 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 11,892 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इंटरएक्टिव सेशन में उद्योगपतियों से हुये संवाद और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों से मध्यप्रदेश को मिली नई गति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को साकार करने में मध्यप्रदेश पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए नीति, नीयत, प्रतिभा, प्रवृत्ति, सुविधा, सामर्थ्य, ऊर्जा, उत्साह, सेवा और सुरक्षा की गारंटी लेकर आगे आया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नई दिल्ली स्थित होटल द लीला पैलेस में आयोजित इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए देश-विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक राज्यों में शामिल है। प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, सुदृढ़ रेल संपर्क, 8 क्रियाशील एयरपोर्ट, 6 अंतदेर्शीय कंटेनर डिपो, एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर और आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना उपलब्ध है। उद्योगों के लिए सवा लाख एकड़ से अधिक लैंड बैंक, पर्याप्त बिजली एवं जल की उपलब्धता तथा नए औद्योगिक क्षेत्रों, फूड पार्क, आईटी पार्क, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत, दीप प्रज्वलन एवं सम्मान के साथ हुआ। इसके बाद सीआईआई दिल्ली स्टेट के चेयरमैन श्री हर्ष वर्धन ने स्वागत उद्बोधन दिया। मध्यप्रदेश में निवेश अवसरों पर आधारित एवी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, निवेश-अनुकूल वातावरण और उपलब्ध अवसरों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं तथा मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉ. इलैयाराजा टी. ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश अवसरों का प्रस्तुतीकरण किया।

इंटरएक्टिव सेशन में एमपीआईडीसी द्वारा सात महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स के साथ राज्य के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने, एसोचैम के साथ उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी बढ़ाने, अमेजन ग्लोबल सेलिंग के साथ प्रदेश के निर्यातकों, एमएसएमई और शिल्पकारों को ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार से जोड़ने तथा पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के माध्यम से वैश्विक निवेश संवर्धन के लिए सहयोग स्थापित किया गया। इसके अलावा अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मैनमेड एवं टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ परिधान, मानव निर्मित फाइबर, तकनीकी वस्त्र एवं कपास आधारित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए विशेष सत्र, बायर-सेलर मीट और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से निवेश संवर्धन पर सहमति बनी।

भौगोलिक बाधाओं को पार कर स्वास्थ्य का भरोसा पहुंचा हर द्वार

मिशन ग्रीन कमांडो बना दूरस्थ वनांचल में सेवा और समर्पण का उदाहरण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड के बोकराटा सेक्टर में संचालित ह्यमिशन ग्रीन कमांडोह्व अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर बसे प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुर्गम एवं वनांचल क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य अमले का समर्पण, प्रशासन की बेहतर कार्ययोजना और जनसहभागिता इस संकल्प को साकार कर रही है। उन्होंने अभियान में शामिल सभी स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वालंटियर्स एवं जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अभियान सिद्ध करता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और समन्वित प्रयासों से सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकती हैं।

बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड का बोकराटा सेक्टर प्रदेश के सबसे दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में से एक है। यहां अनेक फालिया एवं बस्तियां पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर स्थित हैं, जहां तक पहुंचने के लिए वाहन नहीं, बल्कि पैदल सफर ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में गुरुवार को संचालित ह्यमिशन ग्रीन कमांडोह्व ने यह साबित किया कि जब लक्ष्य सेवा का हो तो पहाड़ भी रास्ता बन जाते हैं। स्वास्थ्य टीमों ने कई किलोमीटर पैदल चलकर घर-घर दस्तक दी और यह भरोसा मजबूत किया कि शासन की स्वास्थ्य सेवाएं हर जरूरतमंद तक पहुंचेंगी।

देश के आकांक्षी विकासखंड (एस्पिरेशनल ब्लॉक) पाटी में संचालित यह विशेष अभियान स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक अभिनव पहल है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय समुदाय के समन्वित प्रयासों से यह अभियान सेवा, सुशासन और जनसहभागिता का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरा है।

कलेक्टर बड़वानी श्रीमती जयति सिंह के मार्गदर्शन एवं सतत मॉनिटरिंग में अभियान की विस्तृत माइक्रो प्लानिंग तैयार की गई। स्वास्थ्य, राजस्व एवं पंचायत विभाग सहित विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर प्रत्येक टीम की जिम्मेदारी तय की गई। दुर्गम क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवहन, मानव संसाधन, दवाइयों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित की गई, जिससे अभियान का सफल संचालन संभव हो सका।

अभियान के अंतर्गत लगभग 200 संयुक्त टीमों को मैदानी स्तर पर तैनात किया गया। प्रत्येक टीम में नोडल अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), आशा, एएनएम, आशा कार्यकताओं एवं वालंटियर्स शामिल थे। इन टीमों ने 9 ग्राम पंचायतों के लगभग 2,500 घरों तक पहुंचकर समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं।

प्रदेश के 19 जिलों में 39 नवीन सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण

भोपाल। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को गुरु के प्रति सम्मान, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति आस्था और विद्यालयों में सकारात्मक एवं संस्कारमय शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 15 जुलाई से शुरू हुए आयोजन के दूसरे दिन भी प्रदेश के सभी विद्यालयों के साथ-साथ सांदीपनि विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं मूल्यपरक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एकमहत्वपूर्ण की जा रही है। सांदीपनि उत्सव के अंतर्गत प्रदेश के 19 जिलों में 39 नवीन सांदीपनि विद्यालयों की शुरूआत की जा रही है। गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के दौरान इन विद्यालयों का चरणबद्ध लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, नवाचार आधारित शिक्षण व्यवस्था तथा उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा।

गुरुवार को नरसिंहपुर जिले के शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साईखेड़ा के नवीन भवन का स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में 500 शिक्षक, 5500 छात्र, 2000 पालक एवं 150 जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसके साथ ही शासकीय सादीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बर्रई जिला भोपाल में विधायक श्री रामेश्वर शर्मा एवं स्थानीय गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में सांदीपनि उत्सव का आयोजन हुआ। इसमें 300 से अधिक व्यक्तियों एवं 700 विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति रहीं।

प्रदेश के 3,553 शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने 274 सांदीपनि विद्यालयों का किया शैक्षणिक भ्रमण

भोपाल।प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को गुरु के प्रति सम्मान, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति आस्था और विद्यालयों में सकारात्मक एवं संस्कारमय शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से लोक शिक्षण संचालनालय, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में आयोजित किए जा रहे गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के दूसरे दिन गुरुवार को प्रदेश के 3,553 शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने 274 सांदीपनि विद्यालयों का विशेष शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विद्यालयों की आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का अवलोकन किया। शिक्षकों के साथ संवाद कर नवीन शिक्षण पद्धतियों, नवाचारों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों को सांदीपनि विद्यालयों का परिचय एवं ओरिएंटेशन प्रदान किया गया।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में उपलब्ध विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं का अवलोकन किया।स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगात्मक शिक्षण व्यवस्था और आधुनिक शिक्षण संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों को विद्यालयों में अपनाई जा रही नवाचारी शिक्षण पद्धतियों से भी अवगत कराया गया।

शिक्षकों के साथ संवाद और मार्गदर्शन

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ संवाद कर शिक्षा, अध्ययन की प्रभावी तकनीकों, अनुशासन, व्यक्तित्व विकास तथा भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। शिक्षकों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें लक्ष्य निर्धारण, नियमित अध्ययन तथा नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

बेटों की बेरुखी के बीच वृद्धा को मिला सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार, चार बेटों को भरण-पोषण की जिम्मेदारी

वर्षों पुराने पारिवारिक विवाद का भी हुआ शांतिपूर्ण समाधा

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस की देशभक्ति जनसेवा की भावना के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए पुलिस द्वारा निरंतर संवेदनशील पहल की जा रही है। इसी क्रम में विदिशा पुलिस द्वारा संचालित सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े पारिवारिक, संपत्ति एवं भरण-पोषण संबंधी प्रकरणों की सुनवाई कर आपसी सहमति और समझाइश के माध्यम से प्रभावी समाधान किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में आयोजित सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की बैठक में कुल 08 प्रकरणों की सुनवाई की गई। बैठक में कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा संबंधित पक्षों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना गया और आवश्यक परामर्श एवं समझाइश के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रयास किया गया।

बेटों की बेरुखी के बीच वृद्धा को मिला सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार

एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी की बुजुर्ग पत्नी ने शिकायत की कि पति के निधन के बाद दोनों पुत्रों एवं बहुओं ने उनका साथ छोड़ दिया। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें भीख मांगकर अपने पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। इसके बाद दोनों पुत्र मकान पर अधिकार जताते हुए उन्हें घर से बेदखल करने का प्रयास कर रहे थे। पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनने पर यह स्पष्ट हुआ कि मकान आवेदिका के पति की संपत्ति है। कोर कमेटी की समझाइश के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वृद्धा को किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी तथा उन्हें बिना किसी बाधा के सम्मानपूर्वक मकान में रहने दिया जाएगा। साथ ही, भविष्य में उनकी सेवा एवं देखभाल को ध्यान में रखते हुए संपत्ति संबंधी निर्णय लेने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। शमशाबाद क्षेत्र के एक वरिष्ठ नागरिक ने पुत्र एवं बहू द्वारा मारपीट किए जाने तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा हथियार लेकर धमकाने की शिकायत की थी। पंचायत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विवादित कमरे के मूल्यांकन एवं उचित भुगतान की व्यवस्था का सुझाव दिया गया। दोनों पक्ष इस समाधान पर सहमत हुए तथा पूर्व में दर्ज शिकायतों के संबंध में भी आपसी सहमति से समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

धार जिले के पीएम मित्र पार्क में 90 प्रतिशत भूखंड आवंटित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्यप्रदेश की प्रतिबद्धता और उद्यमियों के हौसले से मिल रहे अच्छे परिणाम

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है किमध्यप्रदेश में गारमेंट सेक्टर में धार जिले का पीएम मित्रा पार्क देश का सबसे बड़ा मित्र पार्क है। इसमें 90 प्रतिशत भूखंड आवंटित हो चुके हैं। यह एक उपलब्धि है। पारंपरिक वस्त्र निर्माण और कपास उद्योग कई दशकों से भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 में टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की संभावनाओं और क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश के धार को देश के पहले पीएम मित्र पार्क की सौगात दी। गारमेंट सेक्टर के इस पार्क के भूमि-पूजन के साथ ही यहां 90 प्रतिशत भू-खंडों का आवंटन भी पूरा कर लिया गया। यह एक रिकॉर्ड है और काम के प्रति राज्य सरकार की दक्षता प्रकट करती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि धार जिले में पीएम मित्र पार्क के आसपास भी निवेशक अब उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन की मांग कर रहे है। प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूलता, कच्चे धागे के लिए माल की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर मध्यप्रदेश निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। प्रदेश की बढ़ती निर्यात क्षमता और रोजगार सृजन की शक्ति से दुनिया

परिचित हो रही है। गारमेंट सेक्टर में निवेशकों की पहल और उद्यमियों का हौसला सराहनीय है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां टेक्ससाइल एंड अपेरल सेक्टर की वैल्यू चेन उपलब्ध है। कपास से धागा तैयार करने, गारमेंट निर्माण और मशीनरी की उपलब्धता मध्यप्रदेश को अग्रणी बनाती है। जैविक कपास के उत्पादन में भी मध्यप्रदेश नंबर वन है। राज्य में केवल कपास का उत्पादन ही नहीं, बल्कि फॉर्म टू फैशन तक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश से 11 हजार 750 करोड़ का टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में निर्यात हुआ है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, विएतनाम, इटली, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में विशेष पहचान बना रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल एवं गारमेंट के सैकड़ों उद्योग संचालित हो रहे हैं। एमएसएमई यूनिट्स की संख्या भी 43 हजार से अधिक हो चुकी है। इस क्षेत्र में 2400 करोड़ रुपए के निवेश के फलस्वरूप 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। धार के पीएम मित्र पार्क से 20 हजार करोड़ से अधिक निवेश का आना और 30 बड़ी कंपनियों का आगमन महत्वपूर्ण है। पीएम मित्र पार्क से अंचल के कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर सेक्टर में आकर्षक नीतियों से विशेष पहचान बना रहा है। राज्य में उद्योगों को आर्थिक सब्सिडी, बिजली आपूर्ति, भूमि आवंटन, स्टांप ड्यूटी में छूट से निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। राज्य में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, कौशल विकास प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। मध्यप्रदेश देश के मध्य में होने और अपनी विशेषताओं के कारण दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में मध्यप्रदेश को प्राप्त निवेश प्रस्ताव में से लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर आ चुका है। वर्ष 2027 में फिर जीआईएस का आयोजन होगा, उम्मीद है कि इसमें निवेश का रिकॉर्ड टूटेगा।

1592 करोड़ रुपए के मिले प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टैक्सटाइल क्षेत्र में आए निवेश प्रस्तावों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत टेक्स 2026 में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से 1592 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से 15 हजार 700 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह के साथ देश के उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड्स के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक चर्चा हुई।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।